

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 5 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक संवत्) [संख्या 48

विषय-सूची हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

हर भाग के पन्ने अलग-	अलग किये	गर्य है,	जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन	सके ।	
विषय	पृष्ट संख्या	वार्षिक	विषय	पृष्ट	वार्षिक
		चन्दा		संख्या	चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0			रु0
भाग १–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति,	_	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर		
स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार	)		प्रदेश		975
जार यूरार ननानरानः ॥।७रा	1323—1350		भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग १—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें,			भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में		
विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर			प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		075
प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व	(		(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
परिषद् ने जारी किया		<b>&gt;</b> 1500	(अ) रिलियट प्रमाटिया यम रिपाट		
	837—918		भाग ६–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		J
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा	_	\
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के			सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले		
अभिनिर्णय			प्रकाशित किये गये		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और	J		(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार			भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं		975
और अन्य राज्यों की सरकारों ने			के ऐक्ट		
जारी किया, हाई कोर्ट की			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ		
विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट			इंडिया की अनुविहित तथा अन्य	319-322	
और दूसरे राज्यों के गजटों का		975	निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	319 322	)
उद्धरण		9/5		_	
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-		
क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका			मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों		
परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत,			और मरने वालों के आँकड़े, फसल		
खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय)			और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	699-727	975
तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	201-202	975	स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र		1425
	201 202	510			==

#### भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

#### विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान अनुभाग] पदोन्नति 02 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1366 / वि०स0 / अधि0 / 6 / 97 टी०सी०—विज्ञप्ति प्रकीर्ण संख्या 1346 / वि०स० / अधि० / 114 / 85, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 द्वारा श्री रवेन्द्र कुमार शुक्ला, उप सचिव के दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उप सचिव के एक रिक्त पद एवं उसकी श्रृंखला में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	श्री बृजेश बाबू श्रीवास्तव, अनुसचिव	उप सचिव	12
2	श्री ध्रुवेश प्रकाश तिवारी, अनुभाग अधिकारी	अनुसचिव	11
3	श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, समीक्षा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	10

उक्त पदोन्नितयां कार्यालय ज्ञाप संख्या 193 / वि०स० / अधि / 105 / 88 टी०सी०, दिनांक 14 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली ज्येष्ठता सूची के अधीन होगी।

सं0 1367/वि०स0/अधि0/6/97 टी०सी०—विज्ञप्ति प्रकीर्ण संख्या 1347/वि०स0/अधि0/92/86, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 द्वारा श्रीमती सुषमा किरन यादव, उप सचिव के दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उप सचिव के एक रिक्त पद एवं उसकी श्रृंखला में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है:

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	श्री सुनील कुमार सिंह, अनुसचिव	उप सचिव	12
2	श्रीमती उर्मिला पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी	अनुसचिव	11
3	श्री सुशील कुमार दीक्षित, समीक्षा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	10

उक्त पदोन्नितयां कार्यालय ज्ञाप संख्या 193 / वि०स० / अधि / 105 / 88 टी०सी०, दिनांक 14 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली ज्येष्ठता सूची के अधीन होगी।

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

#### गोपन विभाग

अनुभाग-1 अधिसूचना 12 नवम्बर, 2020 ई०

सं0 7/1/11/2018-7/2/7/95-सीएक्स0 (1)—मा0 मुख्य न्यायाधीश श्री गोविन्द माथुर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निम्नांकित तालिका में इंगित अविधयों के अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 17 नवम्बर, 2020 से दिनांक 20 नवम्बर, 2020 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से दिनांक 27 नवम्बर, 2020 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 से दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

आज्ञा से, राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव।

#### वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-1

29 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 आडिट-1-555 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री राकेश राम का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री राकेश राम	360300 / 46	कोरारिया, खगवल, चन्दौली, उत्तर प्रदेश-232104	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या आडिट-1-503/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-680/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 10 जुलाई, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-1033/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-158/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आडिट-1-435/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मरण भी कराया गया है किन्तु पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बाद भी श्री राकेश राम द्वारा अपनी स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करायी गयी।

3–अतएव, श्री राज्यपाल जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री राकेश राम पुत्र श्री पन्नर प्रसाद के अभ्यर्थन को निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। सं0 आडिट-1-524 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर सुश्री अर्चना पांडेय का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
सुश्री अर्चना पांडेय	139751 / 3	द्वारा आर0पी0 पाण्डेय, मकान नं0 7/10/9बी0/7, जाप्ती वजीरगंज, नियर पार्वती मैरिज हॉल, पोस्ट-देवकली, अयोध्या, उ0 प्र0-224001	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या आिडट-1-503/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने पर शासन के पत्र संख्या आिडट-1-680/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 10 जुलाई, 2019, पत्र संख्या आिडट-1-1033/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, पत्र संख्या आिडट-1-158/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आिडट-1-435/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मरण भी कराया गया है किन्तु पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बाद भी सुश्री अर्चना पांडेय द्वारा अपनी स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करायी गयी।

3–अतएव, श्री राज्यपाल जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित सुश्री अर्चना पांडेय पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय के अभ्यर्थन को निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 आडिट-1-556 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री सुधीर सिंह का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री सुधीर सिंह	257796 / 25	हृदय भवन, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश-231305	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या आडिट-1-503/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-680/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 10 जुलाई, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-1033/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-158/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आडिट-1-435/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मरण भी कराया गया है किन्तु पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बाद भी श्री सुधीर सिंह द्वारा अपनी स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करायी गयी।

3–अतएव, श्री राज्यपाल जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री हृदय नारायण सिंह के अभ्यर्थन को निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 आडिट-1-534 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री विवेक प्रकाश दुबे का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री विवेक प्रकाश दुबे	105834 / 18	सिन्दुरिया बाजार, महराजगंज, उत्तर	जिला लेखा परीक्षा
		प्रदेश-273207	अधिकारी

2—शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त श्री विवेक प्रकाश दुबे का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ के पद पर विज्ञप्ति / नियुक्ति संख्या 5 / 2019 / आडिट-1-835 / दस-2019-308 (1) / 2014, दिनांक 05 अगस्त, 2019 के माध्यम से नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है। उक्त-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो, यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति / अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3—उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-1034/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-157/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आडिट-1-435/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण हेत् अनुस्मरण भी कराया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि नियुक्ति-पत्र जारी होने के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री विवेक प्रकाश दुबे द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री विवेक प्रकाश दुबे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री विवेक प्रकाश दुबे पुत्र श्री छैल बिहारी दुबे का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28/5/80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6—अतः लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री विवेक प्रकाश दुबे का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री विवेक प्रकाश दुबे द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आडिट-1-534 / दस्त-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री विनय कुमार शर्मा का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री विनय कुमार शर्मा	339514 / 12	द्वारा श्री विनोद कुमार शर्मा, जोगापुर, पोस्ट-पूरे नरसिंह भान, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230001	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त श्री विनय कुमार शर्मा का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बांदा के पद पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 5/2019/आडिट-1-835/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 05 अगस्त, 2019 के माध्यम से नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है। उक्त-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो, यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3—उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन के पत्र संख्या आिट-1-1034 / दस-2019-308 (1) / 2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, पत्र संख्या आिडट-1-157 / दस-2020-308 (1) / 2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आिडट-1-435 / दस-2020-308 (1) / 2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण हेतु अनुस्मरण भी कराया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि नियुक्ति-पत्र जारी होने के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री विनय कुमार शर्मा द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बांदा के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री विनय कुमार शर्मा उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5—सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री राम अभिलाष शर्मा का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28 / 5 / 80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6—अतः लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री विनय कुमार शर्मा का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री विनय कुमार शर्मा द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आडिट-1-534 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री प्रवीण कुमार का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री प्रवीण कुमार	133382 / 12	जघेटा गुज्जर, 169, पांडपुरी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त श्री प्रवीण कुमार का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, शामली के पद पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 5/2019/आडिट-1-835/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 05 अगस्त, 2019 के माध्यम से नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो, यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3—उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-1034/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-157/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आडिट-1-435/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण हेतु अनुस्मरण भी कराया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि नियुक्ति-पत्र जारी होने के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री प्रवीण कुमार द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, शामली के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री प्रवीण कुमार उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5—सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री रकम सिंह का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28 / 5 / 80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6—अतः लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री प्रवीण कुमार का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री प्रवीण कुमार द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आडिट-1-534 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सिम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री वेद प्रकाश यादव का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री वेद प्रकाश यादव	112455 / 18	वार्ड नं0 04, खड्डा, सुभाषनगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274802	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त श्री वेद प्रकाश यादव का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, गोरखपुर के पद पर विज्ञप्ति / नियुक्ति संख्या 8 / 2019 / आडिट-1-927 / दस-2019-308 (1) / 2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के माध्यम से नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो, यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति / अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3—उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-1142/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-157/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आडिट-1-435/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण हेत् अनुस्मरण भी कराया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि नियुक्ति-पत्र जारी होने के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री वेद प्रकाश यादव द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, गोरखपुर के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री वेद प्रकाश यादव उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5—सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री वेद प्रकाश यादव पुत्र श्री चन्द्रदेव यादव का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28 / 5 / 80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6—अतः लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री वेद प्रकाश यादव का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री वेद प्रकाश यादव द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आडिट-1-534 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री आशुतोष कुमार राय का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री आशुतोष कुमार राय	275470 / 23	श्री प्रदीप कुमार राय, नायपुरा, मुफ्तीगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222170	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त श्री आशुतोष कुमार राय का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, बस्ती के पद पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 8/2019/आडिट-1-927/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के माध्यम से नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो, यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3—उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-1142 / दस-2019-308 (1) / 2014, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-157 / दस-2020-308 (1) / 2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आडिट-1-435 / दस-2020-308 (1) / 2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण हेतु अनुस्मरण भी कराया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि नियुक्ति-पत्र जारी होने के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री आशुतोष कुमार राय द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, बस्ती के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री आशुतोष कुमार राय उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5—सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री आशुतोष कुमार राय पुत्र श्री केशव राय का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28 / 5 / 80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6—अतः लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री आशुतोष कुमार राय का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के

उपरान्त इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री आशुतोष कुमार राय द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आडिट-1-534 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री राजेश कुमार का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री राजेश कुमार	078101 / 50	हाउस नं0-3, टाइप-III, पोस्टल कालोनी, राजाजीपुरम्, लखनऊ-226017	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त श्री राजेश कुमार का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बहराइच के पद पर विज्ञप्ति / नियुक्ति संख्या 7/2020/आडिट-1-303/दस-2020-308 (1)/2020, दिनांक 26 जून, 2020 के माध्यम से नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो, यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3—उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-435 / दस-2020-308 (1) / 2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण हेत् अनुस्मरण भी कराया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि नियुक्ति-पत्र जारी होने के 03 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री राजेश कुमार द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बहराइच के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री राजेश कुमार उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5—सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री राजेश कुमार पुत्र श्री शिवपाल का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28 / 5 / 80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6—अतः लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री राजेश कुमार का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री राजेश कुमार द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आडिट-1-534 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री सिन्धु कमल का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से0आ0 का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री सिन्धु कमल	407236 / 11	करगाहर, पोस्ट-करगाहर, रोहतास, बिहार- 821107	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त श्री सिन्धु कमल का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, औरैया के पद पर विज्ञप्ति / नियुक्ति संख्या आडिट-1-1089 / दस-2019-320 (4) / 2018, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो, यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति / अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3—उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-157/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आडिट-1-435/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण हेत् अनुस्मरण भी कराया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि नियुक्ति-पत्र जारी होने के 09 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री सिन्धु कमल द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, औरैया के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री सिन्धु कमल उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री सिन्धु कमल पुत्र श्री राम प्रवेश द्विवेदी का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28/5/80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6—अतः लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री सिन्धु कमल का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री सिन्धु कमल द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आडिट-1-534 / दस-2020-308 (1) / 2014—लोक सेवा आयोग, उ०प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के चयन परिणाम के आधार पर श्री उत्सव मिश्रा का चयन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

नाम	अनुक्रमांक / लो०से०आ० का मेरिट क्रमांक	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4
श्री उत्सव मिश्रा	189395 / 9	3175, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

2—शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त श्री उत्सव मिश्रा का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, अयोध्या के पद पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 8/2019/आडिट-1-927/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के माध्यम से नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो, यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3—उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-1-11142/दस-2019-308 (1)/2014, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019, पत्र संख्या आडिट-1-157/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या आडिट-1-435/दस-2020-308 (1)/2014, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण हेतु अनुस्मरण भी कराया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि नियुक्ति-पत्र जारी होने के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री उत्सव मिश्रा द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, अयोध्या के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री उत्सव मिश्रा उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5—सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित श्री उत्सव मिश्रा पुत्र श्री दुर्गा चरन मिश्रा का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28 / 5 / 80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6—अतः लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री उत्सव मिश्रा का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री उत्सव मिश्रा द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

आज्ञा से, समीर, विशेष सचिव।

## गृह विभाग

[पुलिस सेवायें] अनुभाग-1 प्रोन्नति

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 27/2020/1559/छः पु0से0-1-2020-03 डी०पी०सी०(एचएल)/2020—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रू० 37,400-67,000, ग्रेड पे रू० 8,900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13-क, रू० 1,31,100-2,16,600) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को चयन वर्ष 2020-2021 में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी (वेतनमान रू० 37,400-67,000, ग्रेड पे रू० 10,000, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 14, रू० 1,44,200-2,18,200) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
1	श्री प्रद्युम्न सिंह	53	1991
2	श्री राजेश द्विवेदी	63	1992
3	श्री विजय पाल सिंह	70	1992
4	श्री अजय प्रताप सिंह	73	1992
5	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	75	1992
6	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	76	1992
7	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	77	1992
8	श्री जय प्रकाश सिंह	78	1992
9	श्री दिनेश त्रिपाठी	79	1992
10	श्री त्रिभुवन सिंह	80	1992

2—उपर्युक्त प्रस्तर-1 की तालिका में क्रमांक-8 पर अंकित श्री दिनेश त्रिपाठी की प्रोन्नित सी०जी०एम०, फैजाबाद में लम्बित वाद संख्या 1111/02 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4-उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से, अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव।

#### चिकित्सा विभाग

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

16 मार्च, 2020 ई0

संग 3366 / सेक-2-पांच-19-1(12) / 2013 टी०सी०—उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-4, संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000 ग्रेड पे, रु० 8,700) के चिकित्साधिकारियों को लेवल-5, अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000 ग्रेड पे, रु० 8,900) के पद पर पदोन्नित हेतु दिनांक 05 जनवरी, 2015 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2—विभागीय चयन समिति की बैठक के समय डा० कमल धवन, वरिष्ठता क्रमांक-4261, तत्कालीन वरिष्ठ परामर्शदाता, ए०एच०एम० डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध तत्समय उनकी ब्राडशीट में यह अंकित था कि कार्यालय ज्ञाप-संख्या 3485ए/सेक-2-पांच-14-5(276)/14, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा डा० कमल धवन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित है, जिसके कारण चयन समिति द्वारा उनकी पदोन्नित की संस्तुति 'बन्द लिफाफे' में रखी गयी थी। उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही कार्यालय ज्ञाप-संख्या 31/सेक-2-पांच-16-5(276)/14, दिनांक 06 जनवरी, 2016 द्वारा उन्हें निर्दोष पाते हुये बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दी गयी थी।

3—अतः पदोन्नित सम्बन्धी 'बन्द लिफाफा' खोलते हुए चयन सिमित की संस्तुति के अनुसार डा० कमल धवन (विरिष्ठता क्रमांक-4261) को उनके आसन्न किनष्ठ डा० अनुराग कुमार राजवंशी (विरिष्ठता क्रमांक-4371) की अपर निदेशक के पद पर पदोन्नित की तिथि 28 जनवरी, 2015 से लेवल-5, अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000 ग्रेड पे, रु० 8,900) के पद पर नोशनल प्रोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतदृद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुभाग-8

कार्यालय-ज्ञाप

24 मार्च, 2020 ई0

सं0 982 / पांच-8-2020-जी(290) / 2017 टी०सी-II—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या 219 / 93 / डी०आर० / सेवा-8 / 2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 में 1307 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 5,400 में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद डा० पियूष आनन्द पुत्र श्री काशी नाथ सिंह, म०नं० 34, पेपर मिल कालोनी, निशातगंज, लखनऊ-226006, एम०बी०बी०एस० / एम०डी० (पीडियाट्रिक्स) (चयन क्रमांक एस-93 एवं अनुक्रमांक 53100017267) तथा गृह जनपद चन्दौसी को मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुये

चिकित्सा इकाई सामु० स्वा० केन्द्र, रामनगर, जनपद बाराबंकी में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

- (1) सम्बन्धित चिकित्सक को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) सम्बन्धित चिकित्सक संलग्न निर्धारित शपथ-पत्र पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- (3) सम्बन्धित चिकित्सक को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी०सी०, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (4) सम्बन्धित चिकित्सक नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। योगदान के समय क्रमांक-6 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अविध में अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो नियमानुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
- (5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित चिकित्सक को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
  - (6) सम्बन्धित चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-
  - [1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।
  - [2] अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दिण्डत न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।
  - [3] उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - [4] ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।
  - [5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
  - [6] चल-अचल सम्पति का प्रमाण-पत्र।
  - [7] एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।
  - [8] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।
- (7) सम्बन्धित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 04/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-II, दिनांक 07 फरवरी, 2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।
- (8) सम्बन्धित चिकित्सक पूर्व से पी०एम०एच०एस० संवर्ग में कार्यरत हैं, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

> आज्ञा से, वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव।

#### शुद्धि-पत्र

#### 18 जून, 2020 ई0

सं0 1308 / पांच-8-2020-6(180) / 18—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 739 / पांच-8-2020, दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा डा० निरन्जन कुमार सिन्हा, चिकित्साधिकारी (विरिक्र०-11761) को दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से 17 वर्षीय तृतीत विशिष्ट ए०सी०पी० तथा दिनांक 09 नवम्बर, 2014 से 24 वर्षीय चतुर्थ विशिष्ट ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश में अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा के स्थान पर अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ अंकित हो गया है।

2—शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 मार्च, 2020 में अंकित मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के स्थान पर अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा पढ़ा / समझा जाय।

3—अतएव, शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 739 / पांच-8-2020, दिनांक 19 मार्च, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

> आज्ञा से, शिवगोपाल सिंह, उप सचिव।

#### कार्यालय-ज्ञाप

#### 03 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1718 / पांच-8-2020-जी(290) / 2017 टी०सी-II—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या 219(1) / 93 / डी०आर० / सेवा-8 / 2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 में 565 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 5,400 में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद डा० संदीप कुमार पुत्र श्री मदन राम, पता-167, ग्रा० / पो०-कमरवां, जिला-मऊ, उ०प्र०-276129, एम०बी०बी०एस०, एम०डी० (मेडिसिन) (चयन क्रमांक एस-178 एवं अनुक्रमांक 53100128721) तथा गृह जनपद मऊ को मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुये चिकित्सा इकाई एस०एस०एम०जे० चिकित्सालय, खुर्जा, बुलन्दशहर में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

- (1) सम्बन्धित चिकित्सक को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) सम्बन्धित चिकित्सक संलग्न निर्धारित शपथ-पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- (3) सम्बन्धित चिकित्सक को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी०सी०, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (4) सम्बन्धित चिकित्सक नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। योगदान के समय क्रमांक-6 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अविध में अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो नियमानुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
- (5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित चिकित्सक को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
  - (6) सम्बन्धित चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-
  - [1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

- [2] अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।
- [3] उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
- [4] ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।
- [5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- [6] चल-अचल सम्पति का प्रमाण-पत्र।
- [7] एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।
- [8] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।
- (7) सम्बन्धित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 04/2020/197/चि०-3-2020-जी०-06/2013टी०सी०-II, दिनांक 07 फरवरी, 2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।
- (8) सम्बन्धित चिकित्सक पूर्व से पी०एम०एच०एस० संवर्ग में कार्यरत हैं, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेत् नहीं की जायेगी।
- 2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3—देश में कोरोना की गम्भीर महामारी से लाकडाउन के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1098/पांच-8-2020-जी(290)/2017 टी0सी-II, दिनांक 02 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से, वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव।

अनुभाग-2 23 जुलाई, 2020 ई0 प्रोन्नति

सं0 2031 / सेक-2-पांच-2020-1(6) / 16 टी०सी०-I—उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (अष्टम् संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 10,000) के चिकित्साधिकारी डा० देवेन्द्र सिंह नेगी (विरि० क्र०-5165ख), निदेशक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ को महानिदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 67,000-79,000, पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर प्रोन्नत करते हुये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उपरोक्त पदोन्नति के आदेश विभिन्न मा० न्यायालयों / मा० अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं / निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

3—डा0 देवेन्द्र सिंह नेगी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती के पद / स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

> आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव।

#### 20 अगस्त, 2020 ई0

सं0 2278/सेक-2-पांच-2020-6(144)/2014—उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (अष्टम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4) के चिकित्साधिकारी डा0 बद्री नारायण गुप्ता (वरिष्ठता क्रमांक-5912), तत्कालीन मुख्य

चिकित्साधिकारी, गाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके आसन्न कनिष्ठ डा० कामेश्वर सिंह (विरिष्ठता क्रमांक-5930) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नित की तिथि 11 फरवरी, 2008 से लेवल-4, संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर नोशनल प्रोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से, वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव।

#### 31 अगस्त, 2020 ई0

सं0 2398 / सेक-2-पांच-2020-1(6) / 2016 टी०सी०-I—उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 10,000) के चिकित्साधिकारी डा० राकेश दुबे (विरिष्ठता क्रमांक-5355), निदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को महानिदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 67,000-79,000, पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर प्रोन्नित प्रदान करते हुये महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के पद पर एतदद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उपरोक्त पदोन्नति के आदेश विभिन्न मा० न्यायालयों / मा० अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं / निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

3—डा० राकेश दुबे को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती के पद / स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव।

### कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

अनुभाग-2 कार्यालय-ज्ञाप 04 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 06/2020/320/अस्सी-2-2020-100(9)/2019—कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित की गयी उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 के कार्यान्वयन को मजबूत और निगरानी करने के लिये नीति के प्रस्तर-6.1.2 के प्राविधानानुसार ''राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति'' निम्नानुसार गठित की जाती है :

#### "राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति"

क्र0सं0	समिति का पद	आधिकारिक पदनाम
1	2	3
1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2	उपाध्यक्ष	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
क—	राज्य सरकार के कृषि	निर्यात सम्बन्धी विभाग / संस्थायें—
1	सदस्य	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2	सदस्य	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन
4	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश शासन

1	2	3
5	सदस्य	प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन
6	सदस्य	प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन
7	सदस्य	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश शासन
8	सदस्य	प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन, उत्तर प्रदेश शासन
9	सदस्य	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन
10	सदस्य	प्रमुख सचिव, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
11	सदस्य	निर्यात आयुक्त, निर्यात संवर्धन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार
12	सदस्य	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार
13	सदस्य	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान परिषद् (उपकार), उत्तर प्रदेश
14	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ
15	सदस्य	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश
16	सदस्य	निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ
17	सदस्य	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
	ख-केन्द्र सरकार के निर्यात	सम्बन्धी विभाग / संस्थायें—
1	सदस्य	महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसका प्रतिनिधि
2	सदस्य	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, भारत सरकार
3	सदस्य	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
4	सदस्य	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई०सी०ए०आर०), नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
5	सदस्य	निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई0आई0सी0) के क्षेत्रीय अधिकारी
6	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी / प्रतिनिध, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा
7	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी / प्रतिनिधि, पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवायें, नई दिल्ली
8	सदस्य	भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ०आई०ई०ओ०), नई दिल्ली के प्रतिनिध
	ग–अन्य सदस्य–	
1	सदस्य	1—राज्य सरकार द्वारा नामित 01 (एक) प्रगतिशील किसान पदम श्री राम शरन वर्मा, बाराबंकी ई-मेल vermaagri@gmail.com एवं मों0 नं0 9839376028 2—राज्य सरकार द्वारा नामित 01 (एक) एफ0पी0ओ0 श्री शार्दुल विक्रम चौधरी, निदेशक, जया सीड्स फार्मस प्रोड्यूसर कम्पनी, ग्राम जयापुर, वाराणसी मों0 नं0 8896131008, 9415446090
2	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित दो (02) प्रख्यात निर्यातक 1—श्री शेख इकराम हुसैन, ए-601, गीतिका सी०एच०एस०लि०, प्लाट नं० 105 / 106, सेक्टर-29, वाशी, नवी मुम्बई-400703 ई-मेल sekramhusain@gmail.com एवं मो० नं० 9867632247 2—श्री अजय भालोटिया, फारच्यून राइस लि०, खसरा नं० 378, ग्राम नंगला चमरू, दादरी, गौतमबुद्धनगर-203207 ई-मेल fortuner1@yahoo.co.in एवं मो० नं० 9811880003

1	2	3
3	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित औद्योगिक चैम्बर्स के दो (02) प्रतिनिधि
		1—श्री आलोक शुक्ल, निदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (निकट पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट) मो0 नं0 8009011333
		2—श्री अमित गुप्ता, स्टेट हेड, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्टीज (FICCI), 135, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ ई-मेल amit.gupta@ficci.com एवं मो0 नं0 9793996633

2—अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

> आज्ञा से, डा० देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव।

#### लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-1 अधिसूचना 29 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 158/2020/1369 सा0/23-1-20-89 सा0/20—जनपद-झांसी के भोजला सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-0.545 किमी0) का नाम ''शहीद सुल्तान सिंह'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 447/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-झांसी के भोजला सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-0.545 किमी०) का नामकरण ''शहीद सुल्तान सिंह मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 159/2020/1369 सा0/23-1-20-89 सा0/20—जनपद-मथुरा के बरारी फीडर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-1.00 किमी0) का नाम ''शहीद जितेन्द्र पाल'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 447/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-मथुरा के बरारी फीडर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-1.00 किमी0) का नामकरण ''शहीद जितेन्द्र पाल मार्ग' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 160 / 2020 / 1369 सा0 / 23-1-20-89 सा0 / 20—जनपद-आगरा के फतेहाबाद-रिहावली मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-15.00 किमी0) का नाम ''शहीद बबलू कुमार'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 447 / 02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ / 20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-आगरा के फतेहाबाद-रिहावली मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-15.00 किमी0) का नामकरण ''शहीद बबलू कुमार मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 161/2020/1369 सा0/23-1-20-89 सा0/20—जनपद-प्रयागराज के एन0एच0 भीटी से गुप्ता बस्ती होते हुये कान्तापुर सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-2.00 किमी0) का नाम "शहीद नेबूलाल" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 447/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ट/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्

विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-प्रयागराज के एन०एच० भीटी से गुप्ता बस्ती होते हुये कान्तापुर सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-२.०० किमी०) का नामकरण "शहीद नेबूलाल मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 162/2020/1369 सा0/23-1-20-89 सा0/20—जनपद-बांदा के सहेवा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-2.00 किमी0) का नाम ''शहीद देवेन्द्र मिश्र'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 447/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ट/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-बांदा के सहेवा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-2.00 किमी0) का नामकरण ''शहीद देवेन्द्र मिश्र मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 163 / 2020 / 1369 सा0 / 23-1-20-89 सा0 / 20—जनपद-रायबरेली के वनपुरवा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-0.600 किमी0) का नाम "शहीद महेश कुमार यादव" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 447 / 02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ / 20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-रायबरेली के वनपुरवा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-0.600 किमी०) का नामकरण "शहीद महेश कुमार यादव मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 164/2020/1369 सा0/23-1-20-89 सा0/20—जनपद-प्रतापगढ़ के बेलखरी टिकरी मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.00 किमी0) का नाम ''शहीद अनूप कुमार सिंह'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 447/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के बेलखरी टिकरी मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.00 किमी0) का नामकरण ''शहीद अनूप कुमार सिंह मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 165/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-मथुरा के बाजना से जरैलिया मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-0.255 किमी0) का नाम ''शहीद पंकज कुमार सिंह'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-मथुरा के बाजना से जरैलिया मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-0.255 किमी0) का नामकरण ''शहीद पंकज कुमार सिंह मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 166 / 2020 / 1368 सा0 / 23-1-20-88 सा0 / 20—जनपद-शामली के शामली आदमपुर भौराकला मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-15.30 किमी0) का नाम ''शहीद अमित कुमार'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446 / 02 आई ०डी०एस० प्रकोष्ठ / 20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-शामली के शामली आदमपुर भौराकला मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-15.30 किमी०) का नामकरण ''शहीद अमित कुमार मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 167/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-शामली के पानीपत खटीमा कि0मी0-40 से शामली भौराकला मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-3.30 किमी0) का नाम ''शहीद प्रदीप कुमार'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ट/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-शामली के पानीपत खटीमा कि0मी0-40 से शामली भौराकला मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-3.30 किमी0) का नामकरण ''शहीद प्रदीप कुमार मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 168/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-मैनपुरी के लाखनमऊ से विनायकपुर सोडरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-4.25 किमी0) का नाम ''शहीद श्री राम वकील'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446 / 02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ / 20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-मैनपुरी के लाखनमऊ से विनायकपुर सोडरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-4.25 किमी०) का नामकरण ''शहीद श्री राम वकील मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 169/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-प्रयागराज के टूडिहार से रामचन्द्र पुरा सम्पर्क मार्ग (अमर शहीद के घर तक) (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.60 किमी0) का नाम ''शहीद महेश कुमार यादव'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446/02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-प्रयागराज के टूडिहार से रामचन्द्र पुरा सम्पर्क मार्ग (अमर शहीद के घर तक) (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.60 किमी०) का नामकरण ''शहीद महेश कुमार यादव मार्ग' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 170/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-आगरा के ए०एस०आर० मार्ग से कहरई कौलक्खा होकर ए०डी०आई० मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-3.90 किमी०) का नाम ''शहीद कौशल कुमार रावत'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446/02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-आगरा के ए०एस०आर० मार्ग से कहरई कौलक्खा होकर ए०डी०आई० मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-3.90 किमी०) का नामकरण ''शहीद कौशल कुमार रावत मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 171/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-उन्नाव के पुरवा मझिगवां मार्ग से कउवागढ़ी समाधा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.55 किमी०) का नाम ''शहीद अजीत कुमार आजाद'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446/02 आई0डी०एस० प्रकोष्ट/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-उन्नाव के पुरवा मझिगवां मार्ग से कउवागढ़ी समाधा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.55 किमी०) का नामकरण ''शहीद अजीत कुमार आजाद मार्ग' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 172/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-देविरया के छिपया जयदेव मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.250 किमी०) का नाम "शहीद विजय कुमार मौर्या" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446/02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-देविरया के छिपया जयदेव मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.250 किमी०) का नामकरण "शहीद विजय कुमार मौर्या मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 173 / 2020 / 1368 सा0 / 23-1-20-88 सा0 / 20—जनपद-महराजगंज के हरपुर धनुआडीह से ताल्ही मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-5.20 किमी0) का नाम "शहीद पंकज कुमार त्रिपाठी" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446 / 02 आई0डी0एस० प्रकोष्ठ / 20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-महराजगंज के हरपुर धनुआडीह से ताल्ही मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-5.20 किमी०) का नामकरण ''शहीद पंकज कुमार त्रिपाठी मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 174 / 2020 / 1368 सा0 / 23-1-20-88 सा0 / 20—जनपद-उन्नाव के सिकन्दरपुर करन से अचलगंज पुरवा मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-12.525 किमी०) का नाम ''शहीद विजय कुमार'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446 / 02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ / 20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-उन्नाव के सिकन्दरपुर करन से अचलगंज पुरवा मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-12.525 किमी०) का नामकरण ''शहीद विजय कुमार मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 175/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-कानपुर देहात के ग्राम रैगवॉ सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-0.850 किमी0) का नाम ''शहीद श्याम बाबू' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-कानपुर देहात के ग्राम रैगवॉ सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-0.850 किमी0) का नामकरण ''शहीद श्याम बाबू मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 176/2020/1368 सा0/23-1-20-88 सा0/20—जनपद-कानपुर देहात के डेरापुर मंगलपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-14.500 किमी0) का नाम "शहीद रोहित कुमार यादव" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-कानपुर देहात के डेरापुर मंगलपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-14.500 किमी0) का नामकरण "शहीद रोहित कुमार यादव मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 177 / 2020 / 1368 सा0 / 23-1-20-88 सा0 / 20—जनपद-कन्नौज के हसेरन विधूना मार्ग से अजान सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.00 किमी0) का नाम ''शहीद प्रदीप सिंह'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446 / 02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ / 20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-कन्नौज के हसेरन विधूना मार्ग से अजान सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-1.00 किमी0) का नामकरण ''शहीद प्रदीप सिंह मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 178 / 2020 / 1368 सा0 / 23-1-20-88 सा0 / 20—जनपद-एटा के जैथरा कुरावली मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-14.25 किमी0) का नाम "शहीद सुबोध कुमार सिंह" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 446 / 02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ / 20, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-एटा के जैथरा कुरावली मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-14.25 किमी0) का नामकरण "शहीद सुबोध कुमार सिंह मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से, नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव।

#### परिवहन विभाग

अनुभाग-3 पदोन्नति

05 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 85/2020/3649(2)/30-3-2020-63जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री अरिवन्द कुमार पाण्डेय, अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) को नियमित चयनोपरान्त विशेष सिचव, परिवहन विभाग, उ०प्र० तथा उ०प्र० राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी, वेतन बैण्ड-4 रु० 37,400-67,000 व ग्रेड वेतन रु० 10,000, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-14 के पद पर पदोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय अपनी तैनाती के स्थान पर ही प्रोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे और इनकी तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

> आज्ञा से, राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

#### राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

03 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-933-200 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री योगेन्द्र, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, जालौन (उरई) को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-4, देवरी, झांसी के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-201 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सिंह प्रदीप भुवनेश्वर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, हमीरपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-10, कानपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-202 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राजदीप गुप्ता, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, लिलतपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई घिसौली, लिलतपुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-203 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सत्यव्रत उपाध्याय, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, प्रयागराज को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, बांदा के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-204 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री नितिन श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, कर्वी, चित्रकूट को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, बांदा के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-205 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजय कुमार यादव, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4, देवरिया को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, कानपुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-206 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री दिनेश कुमार-III, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-9, कानपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, उरई के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-207 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के डा0 संजय सिंह-IV, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, फतेहपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, हमीरपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-208 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सूर्यपाल सरोज, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-11, कानपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, महोबा के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-209 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री शेखर सिंह राठौर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, फतेहपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, जालौन के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-210 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री पुनीत कुमार चौबे, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, गोण्डा को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, कानपुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-211 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री कुमार अमित, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर टैक्स आडिट लखनऊ-द्वितीय को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3, कानपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-212 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रद्युम्न कुमार गुप्ता, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-5, अयोध्या को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-4, कानपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-213 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री दीपक कुमार जायसवाल, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, कानपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-5, कानपुर के पद / स्थान पर एतदृद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-214 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अकबर हुसैन, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-7, कानपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-6, कानपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-215 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सन्मति कुमार, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-12, कानपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-7, कानपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-216 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री श्रीधर त्रिपाठी, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-21, कानपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-8, कानपुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-217 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री धनश्याम, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-25, कानपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-9, कानपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-218 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री आशीष गुप्ता, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-27, कानपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-5, लखनऊ के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-219 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनिल कुमार-IX, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, सीतापुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-11, कानपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-220 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुबोध कुमार वर्मा, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, एटा को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-12, कानपुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-221 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अंशुल जगन्नाथ, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-16, कानपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, उन्नाव के पद /स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-222 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री हेमकान्त सिंह, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, औरैया को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, भोगनीपुर (रमाबाईनगर) के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-223 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री घनश्याम द्विवेदी, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6, लखनऊ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, लखनऊ के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-224 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती दीप्ति अग्रवाल, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, लखनऊ के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-225 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रशान्त, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, लखीमपुरखीरी को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3, लखनऊ के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-226 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री पारितोष कुमार मिश्रा, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-14, लखनऊ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-4, लखनऊ के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-227 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री शरद प्रताप सिंह, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-16, लखनऊ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-5, अम्बावाय झांसी के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-228 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री रविकान्त-II, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, हरदोई को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, हरदोई के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-229 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनिल कुमार-X, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-18, लखनऊ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, सीतापुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-230 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रदीप कुमार-VI, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-12, मेरठ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, मेरठ के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-231 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री गजेन्द्र पाल सिंह, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-5, मेरठ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, मेरठ के पद / स्थान पर एतदृद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-232 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अवन कुमार, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, मेरठ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3, मेरठ के पद/स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-233 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री शैलेन्द्र कुमार, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, मेरठ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-4, मेरठ के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-234 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के सुश्री नसीम फातिमा, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, मेरठ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-5, मेरठ के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-235 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रदीप कुमार-IX, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, बड़ौत को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, बागपत के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-236 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनिल कुमार वर्मा, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, मैनपुरी को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, मुरादाबाद के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-237 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री देवेन्द्र कुमार-I, असिस्टेन्ट किमश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि-2, वाणिज्य कर नोयडा को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, मुरादाबाद के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-238 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुबेश तिवारी, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, खुर्जा को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3, मुरादाबाद के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-239 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री कुलदीप सिंह-I, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1,ज्योतिबाफुले नगर (अमरोहा) को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-4, मुरादाबाद के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-240 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सत्येन्द्र प्रताप, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, हसनपुर ज्योतिबाफुले नगर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-5, मुरादाबाद के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-241 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राकेश कुमार उपाध्याय, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, बिजनौर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-6, मुरादाबाद के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-242 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री असित कुमार सिंह, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, नोएडा को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, गजरौला के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-243 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विवेक कुमार-III, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, मुरादाबाद को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, रामपुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-244 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह-II, असिस्टेन्ट किमश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि वाणिज्य कर, मुरादाबाद को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, बिजनौर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-245 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री नीलेश कुमार खरवार, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, चाँदपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, धामपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-246 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री गिरीश चन्द्र सिंह, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, कुशीनगर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, प्रयागराज के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-247 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रदीप कुमार गौतम, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, देवरिया को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, प्रयागराज के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-248 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सन्तोष कुमार सिंह-I, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-11, प्रयागराज को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3, प्रयागराज के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-249 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री भारत भूषण राज, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, कुशीनगर (पडरौना) को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, फतेहपुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-250 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री रामेश्वर दुबे, असिस्टेन्ट किमश्नर, टैक्स आडिट वाणिज्य कर, नोएडा को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, सहारनपुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-251 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राहुल कुमार-I, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, सहारनपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, सहारनपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-252 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मनीष कुमार राय-I, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, देवबंद, सहारनपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3, सहारनपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-253 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री योगेश कुमार मौर्या, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-9, सहारनपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-4, सहारनपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-254 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अहमद यासिर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6, मुजफ्फरनगर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, शामली के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-255 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, शामली को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, शामली के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-256 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मयंक सिंघल, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, गौतमबुद्धनगर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, मुजफ्फरनगर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-257 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री रवि पवॉर, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, मुजफ्फरनगर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, मुजफ्फरनगर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-258 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अरूणेश कुमार सिंह, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, खतौली को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, खतौली के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-259 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-8, गोरखपुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, वाराणसी के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-260 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री वीरेन्द्र कुमार सरोज, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, वाराणसी को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, वाराणसी के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-261 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री महेश चन्द्र, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, वाराणसी को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3, वाराणसी के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-262 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनुज कुमार, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-19, वाराणसी को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-4, वाराणसी के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-263 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री दिनेश कुमार-IV, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, चन्दौली को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, चन्दौली के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-264 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अजय कुमार पाण्डेय-II, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, चन्दौली को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, चन्दौली के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-265 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री पुनीत कुमार तिवारी, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, चन्दौली को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-266 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, देवरिया को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, जौनपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-267 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अरविन्द कुमार पाठक, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-10, वाराणसी को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई, मऊ के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-268 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विवेक कुमार मिश्रा-II, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4, वाराणसी को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, मिर्जापुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-269 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री हर नारायण मिश्रा, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4, मिर्जापुर को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, मिर्जापुर के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-270 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री रवीन्द्र कुमार-II, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, सोनभद्र को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, सोनभद्र के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-271 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, सोनभद्र को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-2, सोनभद्र के पद /स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-272 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अखिलेश गौड, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-9, वाराणसी को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3, सोनभद्र के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-273 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री आदित्य मिश्रा, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-7, अलीगढ़ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर वि0अनु0शा0, रेंज-बी, अलीगढ़ के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-274 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री गौरव कुमार राजपूत, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, गाजियाबाद को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर वि0अनु०शा0, रेंज-बी, गाजियाबाद के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-275 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री भावेन्द्र भाष्कर, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-मवाना, मेरठ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर वि0अनु0शा0, रेंज-ए, मेरठ के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-276 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री लोमेश कुमार, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4, मुरादाबाद को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर वि0अनु0शा0, रेंज-बी, मुरादाबाद के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-277 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री शोभित श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर टैक्स आडिट, वाराणसी-प्रथम को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर वि0अनु0शा0, मिर्जापुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-278 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री आनन्द कुमार सिंह-II, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-5, फिरोजाबाद को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर वि0अनु0शा0, मैनपुरी के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-279 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती शाइस्ता परवीन, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, खुर्जा को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-19, गाजियाबाद के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-280 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती मीरा खण्डेलवाल, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर (पूर्व पदनाम सहायक आयुक्त मनोरंजन कर) मुख्यालय को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6, आगरा के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-281 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती ज्योति धारीवाल, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, मुरादाबाद के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-282 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती स्वाति जायसवाल, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-11, मेरठ को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-19, गाजियाबाद के पद / स्थान पर एतदृद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-283 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती आयुषी दीक्षित, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-8, नोएडा को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद / स्थान पर एतदृद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-284 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राकेश कुमार यादव, असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि वाणिज्य कर, अयोध्या को असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर, लखनऊ के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-285 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनिरूद्ध सिंह, असिस्टेन्ट किमश्नर वाणिज्य कर टैक्स आडिट, इटावा को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद / स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-933-286 / 11-2020-12 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजय कुमार शर्मा, असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, गोण्डा को असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-10, आगरा के पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से, अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—36 हिन्दी गजट—भाग 1—2020 ई०। मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ० प्र0, प्रयागराज।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

### प्रयागराज, शनिवार, ५ दिसम्बर, २०२० ई० (अग्रहायण १४, १९४२ शक संवत्)

#### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया।

## HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

**NOTIFICATION** 

August 06, 2020

**No. 1606/Admin.(Services)-2020**—Sri Satya Vir Singh Yadav, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra *vice* Sri Rajesh Kumar Singh.

He is also appointed under section 5 (2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

**No.** 1607/Admin.(Services)-2020–Sri Rajesh Kumar Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge Agra.

**No.** 1608/Admin.(Services)-2020–Sri Rajesh Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra *vice* Sri Rajendra Prasad Srivastava-III.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act,

1981 as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1609/Admin.(Services)-2020—Sri Rajendra Prasad Srivastava-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Special Judge, Agra for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No.** 1610/Admin.(Services)-2020–Sri Shahid Raza, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Aligarh *vice* Sri Mukesh Kumar Singhal.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Aligarh against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1611/Admin.(Services)-2020**—Sri Mukesh Kumar Singhal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge Aligarh.

**No. 1612/Admin.(Services)-2020**—Sri Narendra Singh, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Special Judge Aligarh for trying cases under

section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No. 1613/Admin.(Services)-2020**—Sri Ram Kesh, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Allahabad *vice* Sri Badri Vishal Pandey.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Allahabad against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1614/Admin.(Services)-2020**—Sri Badri Vishal Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge Allahabad.

No. 1615/Admin.(Services)-2020—Sri Indra Deo Dubey, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Special Judge, Allahabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ram Kishor Shukla.

**No. 1616/Admin.(Services)-2020**—Sri Ram Kishor Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

**No.** 1617/Admin.(Services)-2020–Sri Umesh Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Amroha to be Special Judge, Amroha for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No.** 1618/Admin.(Services)-2020—Sri Rajesh Chaudhary, Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Special Judge Auraiya for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Meenu Sharma.

**No. 1619/Admin.(Services)-2020**–Smt. Meenu Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge, Auraiya.

**No. 1620/Admin.(Services)-2020**—Sri Sheo Chand, Principal Judge, Family Court, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge, Azamgarh.

**No. 1621/Admin.(Services)-2020**—Sri Surendra Nath Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Special Judge, Azamgarh for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Alpana.

**No.** 1622/Admin.(Services)-2020–Smt. Alpana, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 1623/Admin.(Services)-2020—Sri Shailendra Pandey, Additional District & Sessions Judge, Baghpat to be Special Judge, Baghpat for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Abid Shamim.

No. 1624/Admin.(Services)-2020–Sri Abid Shamim, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Baghpat to be Additional District & Sessions Judge, Baghpat.

**No. 1625/Admin.(Services)-2020**–Sri Govind Mohan, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ballia *vice* Sri Pran Vijay Singh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Ballia against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1626/Admin.(Services)-2020**—Sri Pran Vijay Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Ballia.

**No.** 1627/Admin.(Services)-2020–Sri Dinesh Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Special Judge, Ballia for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

No. 1628/Admin.(Services)-2020—Sri Satya Deo Gupta, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Special Judge, Bareilly for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Sunil Kumar Verma.

**No. 1629/Admin.(Services)-2020**—Sri Sunil Kumar Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 1630/Admin.(Services)-2020—Sri Sunil Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Special Judge, Basti for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Abdul Quaiyam.

**No.** 1631/Admin.(Services)-2020–Sri Abdul Quaiyum, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

**No. 1632/Admin.(Services)-2020**—Sri Mukesh Kumar Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Basti *vice* Sri Manmeet Singh Suri.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Basti against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1633/Admin.(Services)-2020**—Sri Manmeet Singh Suri, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

**No. 1634/Admin.(Services)-2020**–Sri Brijesh Kumar Sharma, Additional District & Sessions

Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bijnor *vice* Dr. (Smt.) Manu Kalia.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Bijnor against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1635/Admin.(Services)-2020**–Dr. (Smt.) Manu Kalia, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 1636/Admin.(Services)-2020—Sri Raj Kumar Bansal, Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Special Judge, Bijnor for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Sunil Kumar-V.

**No. 1637/Admin.(Services)-2020**–Sri Sunil Kumar-V, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

**No. 1638/Admin.(Services)-2020**—Court's Notification No. 1469/Admin. (Services)/2020, dated 05-08-2020 is hereby cancelled.

**No. 1639/Admin.(Services)-2020**–Sri Ravi Kant, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Budaun *vice* Sri Shakti Putra Tomar.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1640/Admin.(Services)-2020**—Sri Shakti Putra Tomar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun *vice* Smt. Machala Agarwal.

He is also appointed under section 5 (2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1641/Admin.(Services)-2020–Smt. Machala Agarwal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Special Judge, Budaun for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Dev Raj Prasad Singh.

**No. 1642/Admin.(Services)-2020**—Sri Dev Raj Prasad Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

**No. 1643/Admin.(Services)-2020**—Sri Ram Pratap Singh, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahar *vice* Sri Birendra Kumar Singh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Bulandshahar against the special court created for trying cases under the said Act.

**No.** 1644/Admin.(Services)-2020—Sri Birendra Kumar Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 1645/Admin.(Services)-2020—Sri Rajeev Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Special Judge, Bulandshahar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No.** 1646/Admin.(Services)-2020–In partial modification in the Court's Notification No. 1551/Admin. (Services)/2020, dated 05-08-2020 the name Sri Puneet Kumar Gupta be read as Sri Punit Kumar Gupta.

**No. 1647/Admin.(Services)-2020**—Sri Ajay Kumar, Additional District & Sessions Judge, Deoria to be

Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Deoria in the vacant Court.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Deoria against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1648/Admin.(Services)-2020**—Sri Shailendra Verma, Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Faizabad *vice* Sri Asad Ahmad Hashmi.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Faizabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1649/Admin.(Services)-2020–Sri Asad Ahmad Hashmi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge, Faizabad.

**No.** 1650/Admin.(Services)-2020–Smt. Pooja Singh, Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Special Judge, Faizabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Bhoo Dev Gautam.

**No. 1651/Admin.(Services)-2020**—Sri Bhoo Dev Gautam, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge, Faizabad.

**No. 1652/Admin.(Services)-2020**—Sri Navneet Kumar Giri, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Special Judge, Fatehpur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

No. 1653/Admin.(Services)-2020–Smt. Parul Verma, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Fatehpur in the vacant court.

She is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Fatehpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1654/Admin.(Services)-2020—Sri Ved Prakash Verma, Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddh Nagar to be Special Judge, Gautam Buddh Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No.** 1655/Admin.(Services)-2020–Sri Sunil Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghaziabad *vice* Sri Rajendra Prasad.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Ghaziabad against the special court created for trying cases under the said Act.

**No.** 1656/Admin.(Services)-2020—Sri Rajendra Prasad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1657/Admin.(Services)-2020—Sri Shashi Bhushan Pandey, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Special Judge, Ghaziabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Beena Chaudhary.

**No.** 1658/Admin.(Services)-2020–Sri Gulab Singh-II, Principal Judge, Family Court, Ghazipur to be Special Judge, Ghazipur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Dr. Laxmi Kant Rathaur.

**No. 1659/Admin.(Services)-2020**–Dr. Laxmi Kant Rathaur, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

**No. 1660/Admin.(Services)-2020**—Sri Vishnu Chandra Vaish, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur *vice* Sri Ajay Srivastava.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Ghazipur against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1661/Admin.(Services)-2020**—Sri Ajay Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

**No. 1662/Admin.(Services)-2020**—Smt. Beena Chaudhary, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

**No. 1663/Admin.(Services)-2020**—Sri Prakash Chandra Shukla, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jaunpur *vice* Sri Mahendra Singh-IV.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Jaunpur against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1664/Admin.(Services)-2020**—Sri Mahendra Singh-IV, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

**No. 1665/Admin.(Services)-2020**–Smt. Shazia Nazar Zaidi, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Special Judge, Jaunpur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No. 1666/Admin.(Services)-2020**–Smt. Mamta Gupta, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi *vice* Sri Sanjay Kumar-III.

She is also appointed under section 5 (2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Jhansi against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1667/Admin.(Services)-2020**–Sri Sanjay Kumar-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Jhansi.

**No.** 1668/Admin.(Services)-2020–Km. Indu Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions

Judge/Special Judge, Jhansi vice Sri Jaitendra Kumar.

She is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Jhansi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1669/Admin.(Services)-2020–Sri Jaitendra Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Special Judge, Jhansi for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

No. 1670/Admin.(Services)-2020–Smt. Adesh Nain, Additional District & Sessions Judge, Kannauj to be Special Judge, Kannauj for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No.** 1671/Admin.(Services)-2020–Sri Sunder Lal, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kanpur Nagar *vice* Smt. Vijay Raje Sisodia.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Kanpur Nagar against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1672/Admin.(Services)-2020**—Smt. Vijay Raje Sisodia, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1673/Admin.(Services)-2020—Sri Sanjay Kumar Verma, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Special Judge, Kanpur Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Vinod Kumar Singh-IV.

**No.** 1674/Admin.(Services)-2020—Sri Vinod Kumar Singh-IV, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

**No. 1675/Admin.(Services)-2020**–Sri Kamlesh Kumar Pathak, Additional District & Sessions

Judge, Kaushambi to be Special Judge, Kaushambi for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ramesh Kumar Yadav.

**No. 1676/Admin.(Services)-2020**—Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 1677/Admin.(Services)-2020—Sri Shyam Mohan Jaiswal, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Special Judge, Kushinagar at Padrauna for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Shalini Sagar.

**No. 1678/Admin.(Services)-2020**–Smt. Shalini Sagar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna.

No. 1679/Admin.(Services)-2020-Sri Praveen Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Special Judge, Lakhimpur Kheri for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Sham Kumar.

No. 1680/Admin.(Services)-2020–Sri Sham Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 1681/Admin.(Services)-2020–Sri Aditya Chaturvedi, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (UPSEB), Lucknow *vice* Sri Mohd. Ghazali.

No. 1682/Admin.(Services)-2020-Sri Mohd. Ghazali, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-corruption (UPSEB), Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1683/Admin.(Services)-2020—Sri Vijay Chand Yadav, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow *vice* Sri Padmakar Mani Tripathi.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Lucknow against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1684/Admin.(Services)-2020—Sri Padmakar Mani Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Special Judge, Lucknow for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No.** 1685/Admin.(Services)-2020–In partial modification to Court's Notification No. 1508 Admin. (Services)/2020, dated 05-08-2020 the name 'Sri Ashok Kumr' be read as 'Sri Ashok Kumar'.

**No. 1686/Admin.(Services)-2020**—Sri Rama Kant Prasad, Principal Judge, Family Court, Mahoba to be Additional District & Sessions Judge, Mahoba.

**No.** 1687/Admin.(Services)-2020—Sri Santosh Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Mahoba to be Special Judge, Mahoba for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Avanish Kumar Rai.

**No.** 1688/Admin.(Services)-2020–Sri Avanish Kumar Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mahoba to be Additional District & Sessions Judge, Mahoba.

No. 1689/Admin.(Services)-2020—Sri Ram Ichchhuk Yadav, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Special Judge, Mathura for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Mahendra Nath.

**No. 1690/Admin.(Services)-2020**—Sri Mahendra Nath, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

**No. 1691/Admin.(Services)-2020**—Sri Ram Prakash Pandey, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mathura *vice* Sri Sudama Prasad.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act,

1981 as Special Judge at Mathura against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1692/Admin.(Services)-2020**—Sri Sudama Prasad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

**No. 1693/Admin.(Services)-2020**—Smt. Shabih Zehra, Additional District & Sessions Judge, Mau to be Special Judge, Mau for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Budhi Sagar Mishra.

**No.** 1694/Admin.(Services)-2020–Sri Budhi Sagar Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge, Mau.

No. 1695/Admin.(Services)-2020–Smt. Kiran Bala, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (UPSEB), Meerut *vice* Sri Gyan Prakash Singh.

**No.** 1696/Admin.(Services)-2020—Sri Gyan Prakash Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-corruption (UPSEB), Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

**No. 1697/Admin.(Services)-2020**—Sri Ratnesh Mani Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Meerut *vice* Sri Pankaj Misra.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Meerut against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1698/Admin.(Services)-2020**—Sri Pankaj Misra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

**No. 1699/Admin.(Services)-2020**–Sri Mohd. Ghulamul Madar, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Special Judge, Meerut for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Mohd. Asharaf Ansari.

**No. 1700/Admin.(Services)-2020**—Sri Mohd. Asharaf Ansari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 1701/Admin.(Services)-2020-Sri Anil Kumar Vashistha, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Special Judge, Moradabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No. 1702/Admin.(Services)-2020**–Sri Satya Prakash Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Moradabad in the vacant court.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Moradabad against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1703/Admin.(Services)-2020**–Sri Sita Ram, Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Special Judge, Pilibhit for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Abhishek Pandey.

**No.1704/Admin.(Services)-2020**–Sri Abhishek Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge, Pilibhit.

**No. 1705/Admin.(Services)-2020**–Smt. Alka Bharti, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge, Pilibhit.

No. 1706/Admin.(Services)-2020-Sri Rajeev Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pilibhit in the vacant court.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act,

1981, as Special Judge at Pilibhit against the Special Court created for trying cases under the said Act.

**No. 1707/Admin.(Services)-2020**—Sri Vikas Verma, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pratapgarh *vice* Sri Mahesh Kumar.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Pratapgarh against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1708/Admin.(Services)-2020**–Sri Mahesh Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 1709/Admin.(Services)-2020-Sri Manoj Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Special Judge, Pratapgarh for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Santosh Kumar Tiwari.

**No. 1710/Admin.(Services)-2020**–Sri Santosh Kumar Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

**No. 1711/Admin.(Services)-2020**–Sri Hira Lal-III, Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Raebareli *vice* Sri Zaigam Uddin.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Raebareli against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1712/Admin.(Services)-2020**—Sri Zaigam Uddin, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge, Raebareli.

**No. 1713/Admin.(Services)-2020**–Sri Arun Kumar Mall, Additional District & Sessions Judge,

Raebareli to be Special Judge, Raebareli for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No.** 1714/Admin.(Services)-2020—Sri Ahasan Husain, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Saharanpur *vice* Sri Krishna Chandra Pandey.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Saharanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1715/Admin.(Services)-2020**—Sri Krishna Chandra Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

**No. 1716/Admin.(Services)-2020**—Sri Rajesh Kumar-V, Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar.

No. 1717/Admin.(Services)-2020-Sri Jainuddin Ansari, Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar to be Special Judge, Sant Kabir Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No. 1718/Admin.(Services)-2020**—Sri Rakesh Kumar Singh-II, Principal Judge, Family Court, Shravasti at Bhinga to be Additional District & Sessions Judge, Shravasti at Bhinga.

**No. 1719/Admin.(Services)-2020**—Sri Dhruva Kumar Tiwari, Principal Judge, Family Court, Siddharth Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar.

**No. 1720/Admin.(Services)-2020**—Sri Ram Suchit, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sitapur *vice* Sri Surendra Prasad Yadav.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sitapur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1721/Admin.(Services)-2020-Sri Surendra Prasad Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Special Judge, Sitapur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

**No. 1722/Admin.(Services)-2020**—Sri Ashok Kumar-XI, Principal Judge, Family Court, Sonbhadra to be Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra.

No. 1723/Admin.(Services)-2020–Sri Santosh Kumar Gautam, Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra to be Special Judge, Sonbhadra for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Netrapal Singh.

**No. 1724/Admin.(Services)-2020**—Sri Netrapal Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra to be Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra.

**No.** 1725/Admin.(Services)-2020–Sri Bhupendra Rai, Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Unnao *vice* Sri Kunal Vepa.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Unnao against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1726/Admin.(Services)-2020–Sri Kunal Vepa, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Special Judge, Unnao for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

No. 1727/Admin.(Services)-2020-Sri Sarvesh Kumar Pandey-II, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (UPSEB), Varanasi *vice* Sri Rajeshwar Shukla.

No. 1728/Admin.(Services)-2020–Sri Rajeshwar Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-corruption (UPSEB), Varanasi to be Special Judge, Varanasi for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

No. 1729/Admin.(Services)-2020-Sri Ashok Kumar Singh Yadav, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Varanasi *vice* Sri Rajiv Kamal Pandey.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Varanasi against the special court created for trying cases under the said Act.

- **No.** 1730/Admin.(Services)-2020–Sri Rajiv Kamal Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.
- No. 1731/Admin.(Services)-2020—In partial modification in the Court's Notification No. 1572/Admin.(Service)/2020,dated August 05, 2020, the designation/words "Chairman, Administrative Tribunal-III and Member, Administrative Tribunal-III, Lucknow" be read as "Chairman, Administrative Tribunal-III and Member, Administrative Tribunal-III and Member, Administrative Tribunal-I, U.P., Lucknow".
- **No. 1732/Admin.(Services)-2020**—Pursuant to Government Notification no. 15/2020/1017/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, June 30, 2020, Sri Ashish Kumar Chaurasia, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.
- **No. 1733/Admin.(Services)-2020**—Pursuant to Government Notification no. 15/2020/1017/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, June 30, 2020, Dr. (Smt.)

Jaya Pathak, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional Principal Judge, Family Court, Sitapur.

- No. 1734/Admin.(Services)-2020–Sri Vatsal Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Special court no. 2 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur to be Registrar (Judicial) (Listing), High Court of Judicature at Allahabad.
- No. 1735/Admin.(Services)-2020–Sri Nitish Kumar Rai, Joint Registrar (Judicial) (Admin.), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow to be Registrar (Judicial) (Admin.), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.
- No. 1736/Admin.(Services)-2020—Dr. Satyawan Singh, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Registrar (Judicial) (Listing), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.
- **No.** 1737/Admin.(Services)-2020–Sri Pushpender Singh, Joint Registrar (Judicial) (CPC), High Court of Judicature at Allahabad to be Registrar (Judicial) (CPC), High Court of Judicature at Allahabad.
- **No. 1738/Admin.(Services)-2020**—Sri Brahmatej Chaturvedi, Joint Registrar (Judicial) (Computer), High Court of Judicature at Allahabad to be Registrar (Judicial) (Computer), High Court of Judicature at Allahabad.
- **No.** 1739/Admin.(Services)-2020–Sri Ram Bilash Singh, Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of U.P., Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.
- **No. 1740/Admin.(Services)-2020**—Sri Manoj Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddh Nagar.

#### August 18, 2020

No. 1741/Admin.(Services)-2020-Sri Yogesh Kumar Yadav, Secretary (Full Time) District Legal Services Authority, Agra to be Additional Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Sri Sundar Pal.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Agra.

**No.** 1742/Admin.(Services)-2020–Sri Sundar Pal, Additional Chief Judicial Magistrate, Agra to be Special Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Sri Vinay Kumar Singh-IV.

No. 1743/Admin.(Services)-2020–Sri Vinay Kumar Singh-IV, Special Chief Judicial Magistrate, Agra to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Agra in the vacant court.

**No.** 1744/Admin.(Services)-2020–The Court's Notification no. 1381/Admin. (Services)-2020 dated July 23, 2020 regarding posting of Sri Ravi Kant-II is hereby cancelled.

#### August 19, 2020

No. 1745/Admin.(Services)-2020–In exercise of the Powers conferred under clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Abhimanyou Singh, Additional District & Sessions Judge (Pocso), Kushinagar at Padrauna, till new District & Sessions Judge, assumes charge of his office.

#### August 26, 2020

No. 1746/Admin.(Services)/2020–Pursuant to the Government Notification No. 22/2020/1287/Saat-Nyaya-2-2020-58G/2001, dated August 21, 2020, Sri Nirbhay Narain Rai, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Siddhartha Nagar to be Additional Principal Judge, Family Court, Siddhartha Nagar.

No. 1747/Admin.(Services)/2020—Pursuant to the Government Notification No. 22/2020/1287/Saat-Nyaya-2-2020-58G/2001, dated August 21, 2020, Smt. Rakhi Dixit, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional Principal Judge, Family Court, Budaun.

No. 1748/Admin.(Services)/2020—Pursuant to the Government Notification No. 22/2020/1287/Saat-Nyaya-2-2020-58G/2001, dated August 21, 2020, Smt. Lovey Yadav, Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional Principal Judge, Family Court, Mainpuri.

#### August 27, 2020

No. 1749/Admin.(Services)-2020–Sri Sharad Kumar Chaudhary, Additional Chief Judicial Magistrate (Special Court Ayodhya Prakaran), Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Smt. Purnima Sagar.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Lucknow.

No. 1750/Admin.(Services)-2020—Smt. Purnima Sagar, Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

#### August 31, 2020

**No. 1751/Admin.(Services)-2020**—Sushri Deekshi Chaudhary, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Jasrana (Firozabad) to be Civil Judge, (Junior Division), Firozabad *vice* Sushri Rashi Raheja.

No. 1752/Admin.(Services)-2020–Sushri Rashi Raheja, Civil Judge, (Junior Division), Firozabad is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Firozabad *vice* Sri Mimoh Yadav.

**No.** 1753/Admin.(Services)-2020–Sri Mimoh Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Firozabad to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Firozabad.

By order of the Court, AJAY KUMAR SRIVASTAVA-I, Registrar General.

# जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

12 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 1226/8 (भू०अ०)/न०म०पा०-प्रथम/लखनऊ—लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जन से छूटी जनपद लखनऊ, तहसील लखनऊ के ग्राम मलेशेमऊ की 0.338 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 950/8 (भू०अ०)/न०म०पा०-प्रथम/लखनऊ, दिनांक 04 जून, 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 15 जून, 2020 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04 सितम्बर, 2020 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला लखनऊ, तहसील सदर के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वावन एवं पुनर्व्ववस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जन से छूटी हुई ग्राम मलेशेमऊ की भूमि अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है):

अनुसूची-क (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	मलेशेमऊ	173	0.3380

अनुसूची-ख (विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

अभिषेक प्रकाश, जिला कलेक्टर, लखनऊ।

05 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1329 / (भू०अ०) / न०म०पा०-प्रथम / लखनऊ—''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि उ०प्र० एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में ग्राम चांद सरांय की 0.3672 हे0, बेली की 0.7893 हे0, रसूलपुर आशिकअली की 1.1625 हे0, शहजादेपुर की 0.4587 हे0, आदमपुर नौबस्ता की 0.3158 हे0, शिवलर

की 0.4210 हे0, देहरामऊ की 0.3276 हे0, महुराकला की 0.7293 हे0 व पहासा की 0.4124 हे0, कुल 4.9838 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से पूर्व राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2019 को अनुमोदित किया गया था।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार था-

समिति यह अनुभव करती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लोक उद्देश्यों की सेवा करेगा तथा इसका निर्माण न केवल क्षेत्रीय एकीकरण का कार्य करेगा बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिये सहायक होगा।

भूमि प्रदान करने वाले काश्तकारों से हुये विचार विमर्श से यह प्रतीत होता है कि वे अपनी भूमि परियोजना को देने के लिये सहमत हैं, यदि भूमि का उचित मुआवजा उन्हें प्रदान किया जाये। ग्रामीण इस बात से भी सहमत हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लाभदायी होगा।

ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि सर्किल रेट के आधार पर प्रस्तावित मुआवजें बाजार दर से काफी कम है। इसलिये सिमित दृढ़ता से अपने निष्कर्षों के आधार पर सिफारिस करती है कि मुआवजे की दर को विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में बढ़ाया जाना चाहिये कि प्रभावित क्षेत्र के सर्किल रेट दिसम्बर, 2015 से बढ़ाये नहीं गये हैं और प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण वर्ष, 2018 में किया जा रहा है।

समिति द्वारा यह भी अनुभव किया गया है कि ग्रामीणों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचने के लिये मुआवजे की दर एक ही क्षेत्र में समान होनी चाहिये और यह भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 (बी) में वर्णित भूमि के मूल्य के निर्धारण या अवधारण करने के मापदण्ड के अनुरूप भी होगा।

4—समिति की उक्त संस्तुति के सम्बन्ध में यूपीडा के पत्र सं0 2907 / यूपीडा 18 / 548-(01)-II (भू-अर्जन), दिनांक 14 सितम्बर, 2018 में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के उपरोक्तानुसार प्रभावित क्षेत्रों के सर्किल रेट पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कर एवं निबंधन विभाग / जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार करने पर विचार किया जायेगा।

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 में कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण उल्लिखित किया गया है, जिसके बिन्दु-ख में उल्लेख है कि निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिये औसत विक्रय कीमत कलेक्टर द्वारा प्रतिकर का निर्धारण किया जायेगा।

इसी क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन की कार्यवाही के उपरान्त वर्तमान में इसी परियोजना हेतु अनुसूची में वर्णित अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

5-भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

6—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित कि	ये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5		6
						हेक्टेयर
लखनऊ	मोहनलालगंज	गोसाईंगंज	चांद सराय	229		0.0660
				242		0.0300
				251		0.0672
				315		0.0700
				316		0.1160
				585		0.0180
					योग	0.3672

1	2	3	4	5		6
						हेक्टेयर
लखनऊ	मोहनलालगंज	गोसाईंगंज	बेली	553		0.0080
		•		556		0.0300
				557		0.0048
				583		0.0438
				595		0.0150
				596		0.0180
				597		0.0311
				598		0.0072
				599		0.0040
				603		0.0560
				604		0.0072
				637		0.0240
				638		0.0400
				639		0.0288
				640		0.0228
				641		0.1230
				643		0.0024
				644		0.0600
				645		0.0300
				640 / 945		0.0280
					योग	0.7893
			रसूलपुर	420		0.0050
			आशिकअली	421		0.0240
				426		0.0010
				458		0.1996
				459		0.0521
				476		0.0210
				477		0.009
				480		0.0072
				481		0.0484
				483		0.0391
				485		0.0014
				486		0.0990
				489		0.0760
				490		0.0670
				491		0.0074
				492		0.0012
				495		0.064
				523		0.0030
				768		0.1824
				784		0.0684
				785		0.0768
				786		0.1085
				490 / 792		0.0010
					योग	1.1625

1	2	3	4	5		6
						हेक्टेयर
लखनऊ	मोहनलालगंज	गोसाईंगंज	शहजादेपुर	76		0.0120
			_	100		0.0364
				101		0.0347
				102		0.1230
				103		0.0210
				106		0.0176
				113		0.0250
				115		0.0350
				184		0.0930
				187		0.0510
				191		0.0100
					योग	0.4587
			आदमपुर	18		0.2990
			नौबस्ता	527		0.0048
				530		0.0120
					योग	0.3158
			शिवलर	1345		0.1230
				1449		0.2980
					योग	0.4210
			देहरामऊ	36		0.2300
				39		0.0976
					योग	0.3276
			महुराकलां	1769		0.2818
				1770		0.4475
					योग	0.7293
			पहासा	3		0.2734
				325		0.1390
					योग	0.4124
					कुल योग	4.9838

7—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

8—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

मनीष कुमार नाहर, कलेक्टर, लखनऊ। सं0 1332/8 (भू030)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ—लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित सार्वजिनक प्रयोजन यथा मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनिशप के लिये जनपद लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर के ग्राम सरसंवा की 1.7646 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 612/8 (भू030)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 23 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04 नवम्बर, 2020 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला लखनऊ, तहसील सदर के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनिशप के लिये अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है):

अनुसूची-क (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भृमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी	लखनऊ	सरंसवा	153	0.3730
	नगर			450	0.6774
				457	0.4050
				468-मि0	0.2880
				468-मि0	_0.0126
				योग	Т 1.7560

अनुसूची-ख (विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

अभिषेक प्रकाश, जिला कलेक्टर, लखनऊ।

# ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

05 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 64/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012)

			•	١.
-21	ਜ	J	7	T
V	ľ	N	. ч	ı
	J	•	•	

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	भौरदा	927	0.253	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				भौरदा				प्रदेश को कचनौंदाकलां
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 65/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /			श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	बांसी	अंधेर	950 / 1-मि0	0.250	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				अंधेर				प्रदेश को लागौन ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 66 / आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258 / रा0-1 / 16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012)

			•	`
.य	ਜ	स	च	T
VI	٠,	N١	ч	
	- 2		`	

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	बुढ़वार	1312-मि0	0.283	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				समाज				प्रदेश को जाखलौन-
				बुढ़वार				विरधा ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 67/आट-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	पड़ोरिया	584-मि0	0.162	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				समाज				प्रदेश को जाखलौन-
				पड़ोरिया				विरधा ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 68 / आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258 / रा0-1 / 16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012)

			•	`
.य	ਜ	स	च	T
VI	٠,	N١	ч	
	- 2		`	

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	मैनवार	74 / 2-मि0	0.250	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				समाज				प्रदेश को मसौरा-
				मैनवार				सिंधवाहा ग्राम समूह
								पाइप पेयजल योजना
								हेतु ।

सं0 69/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	गनगौरा	550/3	0.162	6-4-	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम			पत्थर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				समाज				प्रदेश को जाखलौन-
				गनगौरा				विरधा ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं० ७७ / आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२१)—शासनादेश संख्या २५८ / रा०-१ / १६(१)-७३, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन् २०१२)

			_0	
.य	7	У	711	
V	્ય	٠,	ุฯเ	
	•		••	

					3 6			
<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	खितवांस	1232/5	0.160	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				समाज				प्रदेश को मसौरा-
				खितवांस				सिंधवाहा ग्राम समूह
								पाइप पेयजल योजना
								हेतु ।

सं0 71/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	विरधा	1083-मि0	0.160	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				समाज				प्रदेश को जाखलौन-
				विरधा				विरधा ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

06 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 80 / आठ-एल०ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258 / रा०-1 / 16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012)

			•	`
.य	ਜ	स	च	T
VI	٠,	N١	ч	
	- 2		`	

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	कल्यानपुरा	2060/2	0.405	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				समाज				प्रदेश को कचनौंदाकलां
				कल्यानपुरा				ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं० 81/आट-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२1)—शासनादेश संख्या २५८/ रा०-1/16(1)-73, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन् २०१२) की धारा ५९ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ३५/७४०/एक-१-२०१६-२०(५)/२०१६, दिनांक ०३ जून, २०१६ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०५ मार्च, १९७४ के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-६ में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	मैलवाराकलां ग्राम समाज मैलवाराकलां	128 / 14	0.255	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कचनौंदाकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं० 82 / आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२१)—शासनादेश संख्या २५८ / रा०-१ / १६(१)-७३, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते ह्ये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन् २०१२)

			•	`
.ध	ਜ	स	7	П
VI	٦.	N	. ч	ш
			`	

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	जमुनधानाखुर्द	178/2	0.162	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				जमुनधानाखुर्द				प्रदेश को कचनौंदाकलां
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं० 83 / आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२1)—शासनादेश संख्या २५८ / रा०-1 / 16(1)-73, दिनांक ०५ मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन् २०१२) की धारा ५९ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ३५ / ७५० / एक-१-२०१६-२०(५) / २०१६, दिनांक ०३ जून, २०१६ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०५ मार्च, १९७४ के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-६ में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

<u></u> 큙0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	नयागांव	1021 / 1	0.093	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				नयागांव				प्रदेश को जाखलौन-
								विरधा ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 84/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त

# अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u> </u>						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	खजुरिया	610/7	0.089	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				खजुरिया				प्रदेश को मसौरा-
								सिंधवाहा ग्राम समूह
								पाइप पेयजल योजना
								हेतु ।

सं० 85/आट-एल०ए०सी०-पुर्न० (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	बांसी	अड़वाहा	1200 / 1	0.162	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज	1200/2	0.101	बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				अड़वाहा	_		_	प्रदेश को लागौन ग्राम
					योग	0.263		समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं० 86/आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२१)—शासनादेश संख्या २५८/ रा०-१/१६(१)-७७, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन् २०१२) की धारा ५० की उपधारा (४) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	खिरियाछतारा ग्राम समाज खिरियाछतारा	54/3	0.162	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कचनौंदा- कलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 87/आट-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

# अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	टोरिया	585/3	0.202	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				जैरवारा				प्रदेश को लागौन ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 88/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	खोंखरा	206	0.235	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				खोंखरा				प्रदेश को कचनौंदाकलां
								ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 89/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	खडेरा	138-मि0	0.162	बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			5-3-ड़,	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				खडेरा				प्रदेश को मसौरा-
								सिंदवाहा ग्राम समूह
								पाइप पेयजल योजना
								हेतु ।

सं0 90/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा /	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
VIO				स्थानीय प्राधिकारी	VIGAI		प्रकृति	जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मडावरा	मडावरा	जलंधर	122/31	0.251	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				जलंधर				प्रदेश को सैदपुर-कुम्हैडी
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 91/आट-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

# अनुसूची

<u></u> 큙0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
				स्थानीय			प्रकृति	जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	रारा	303/6	0.275	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				रारा				प्रदेश को मऊ ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 92/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016

अ	नस	ची
Ο,	_ Y ^ 1	11

ग्राम समाज जलापूर्ति विभाग, उत्त गदयाना प्रदेश को कचनौंदाकल ग्राम समूह पाइप	क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1 ललितपुर तालबेहट बानपुर गदयाना 1078/3 0.262 6-4-पत्थर नमामि गंगे तथा ग्रामीप ग्राम समाज गदयाना प्रदेश को कचनौंदाकल ग्राम समूह पाइप	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम समाज जलापूर्ति विभाग, उत्त गदयाना प्रदेश को कचनौंदाकल ग्राम समूह पाइप							हेक्टेयर		
गदयाना प्रदेश को कचनौंदाकल ग्राम समूह पाइप	1	ललितपुर	तालबेहट	बानपुर	गदयाना	1078/3	0.262	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
ग्राम समूह पाइप					ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
					गदयाना				प्रदेश को कचनौंदाकलां
पेयजल योजना हेत्।									ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेत्।

सं0 93/आट-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	तालबेहट अन्दर ग्राम समाज खांदी	7877-मि0	0.283	6-4-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कड़ेसराकलां ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 94/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	दिदौरा	101	0.160	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				पूराकलां				प्रदेश को बदनपुर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं० 95 / आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२१)—शासनादेश संख्या २५८ / रा०-१ / १६(१)-७७, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन् २०१२) की धारा ५० की उपधारा (४) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ३५ / ७४० / एक-१-२०१६-२०(५) / २०१६, दिनांक ०३ जून, २०१६ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०५ मार्च, १९७४ के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-६ में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

# अनुसूची

					3 6			
क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	उगरपुर	72 / 4-मि0	0.202	6-4-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				उगरपुर				प्रदेश को बदनपुर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं० 96/आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२1)—शासनादेश संख्या २५८/ रा०-1/16(1)-73, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८८, सन् २०१२) की धारा ५९ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ३५/७४०/एक-१-२०१६-२०(५)/२०१६, दिनांक ०३ जून, २०१६

# अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	सारसेड	754	0.250	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				सारसेड				प्रदेश को बदनपुर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 97/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	हजारिया ग्राम समाज बघौरा	268	0.160	6-4-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बदनपुर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं० 98/आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२1)—शासनादेश संख्या २५८/ रा०-1/16(1)-73, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८८, सन् २०१२) की धारा ५० की उपधारा (४) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ३५/७४०/एक-१-२०१६-२०(५)/२०१६, दिनांक ०३ जून, २०१६

# अनुसूची

क्रo	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	विरधा	2206/2-	0.162	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज	मि0		बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				विरधा				प्रदेश को बदनपुर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं० 99/आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२1)—शासनादेश संख्या २५८/ रा०-1/16(1)-७७, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८८, सन् २०१२) की धारा ५९ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ३५/७४०/एक-१-२०१६-२०(५)/२०१६, दिनांक ०३ जून, २०१६ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०५ मार्च, १९७४ के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-६ में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

# अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	करेंगा	540-मि0	0.250	6-4-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				चुरावनी				प्रदेश को बदनपुर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 100/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न

अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	बांसी	बिनैकामाफी	67/2	0.160	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				सिरसी				प्रदेश को लागौन ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

# 07 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 125/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

# अनुसूची

					<b>O</b> 4.			
क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	गेवरा गुन्देरा	1411/2	0.162	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				गेवरा गुन्देरा				प्रदेश को बदनपुर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 126/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	मड़ावरा	गौना	597 / 3-	0.250	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज	मि0		बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				गौना				प्रदेश को गौना-नाराहट
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 127/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	बालाबेहट	रमपुरा	20-मि0	0.162	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				सैपुरामुजप्ता				प्रदेश को धौर्रा-बालाबेहट
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 128/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	निबौआ	279	0.253	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				निबौआ				प्रदेश को जाखलौन-
								विरधा ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 129/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	बूचा	523/3	0.251	5-3-(ड़),	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			(बंजर)	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				बूचा				प्रदेश को लागौन ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 130/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	सतरवांस	1549	0.255	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				सतरवांस				प्रदेश को मसौरा-सिंधवाहा
								ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 131/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	बछलापुर	273/3	0.255	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				बछलापुर				प्रदेश को जाखलौन-
								विरधा ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 132/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	लहरैन	342	0.160	5-1-नवीन	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			परती	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				लहरैन				प्रदेश को सोजना-गुढ़ा
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 133/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	बड़ोखरा	390 / 1-मि0	0.160	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				बड़ोखरा				प्रदेश को बिल्ला-मोगान
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 134/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	मैनवार	487 / 3-मि0	0.160	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				मैनवार				प्रदेश को मसौरा-सिंधवाहा
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 135/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	सोजना	2236/3	0.200	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				सोजना				प्रदेश को सोजना-गुढ़ा
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 136/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	किसरदा	346	0.160	5-1-नवीन	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			परती	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				किसरदा				प्रदेश को मसौरा-सिंधवाहा
								ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 137/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	गुगरवारा	982	0.245	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				गुगरवारा				प्रदेश को कचनौंदाकलां
								ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 138/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा /	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय प्राधिकारी			प्रकृति	की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	रमगढ़ा	1349 / 4-मि0	0.250	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				रमगढ़ा				प्रदेश को सुकलगुवां ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 139/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	नड़ारी	170 / 6-मि0	0.162	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				खुटगुवां				प्रदेश को टोरी ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 140/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	सुनौनी	73-मि0	0.250	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				भीकमपुर				प्रदेश को सुकलगुंवा ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 141/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	पिपरट	1024	0.250	नवीन	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			परती-5(1)	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				रखवारा				प्रदेश को सैदपुर-कुम्हैडी
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 142/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	बम्हौरीखुर्द	424 / 1	0.162	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				बम्हौरीखुर्द				प्रदेश को टोरी ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 143/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	मदनपुर	727/3	0.161	5-3 (ड़)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			(बंजर)	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				मदनपुर				प्रदेश को सैदपुर-कुम्हैडी
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 144/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	भीकमपुर	95/2	0.250	बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			5-3 (ड़)	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				भीकमपुर				प्रदेश को टौरी ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 145/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	छपरा	113-मि0	0.150	बंजर-5-3 (ड़)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				मड़ावरा				प्रदेश को मड़ावरा ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 146/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	विघाई	170-मि0	0.160	बंजर-5-3-ङ	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				छितरापुर				प्रदेश को सुकलगुंवा ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 147/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	सैदपुर	1372/2-	0.250	5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज	मि0			जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				सैदपुर				प्रदेश को सैदपुर-कुम्हैड़ी
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 148/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	उल्दनाखुर्द	37-मि0	0.160	5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				उल्दनाखुर्द				प्रदेश को टोरी ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

# 22 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 247/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	बिल्ला	631-मि0	0.161	6-2-अकृषिक	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			भूमि पत्थर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				बिल्ला				प्रदेश को बिल्ला-मोगान
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं० २४८ / आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२१)—शासनादेश संख्या २५८ / रा०-१ / १६(१)-७३, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन्

# अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा /	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	भौंड़ी	527	0.160	6-2-	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बहुउद्देशीय	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				भौंड़ी			प्रयोजन	प्रदेश को सोजना-गुढ़ा
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 249/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	मड़ावरा	अर्जुनखिरिया	63 / 1463	0.250	6-2-	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बहुउद्देशीय	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				अर्जुनखिरिया			प्रयोजन	प्रदेश को गौना-नाराहट
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं० २५० / आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२१)—शासनादेश संख्या २५८ / रा०-१ / १६(१)-७३, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन्

## अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
,						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	धौरीसागर ग्राम समाज धौरीसागर	788 / 3- 甲0	1.000	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को टोरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

#### 24 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 2987/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

	_							
क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानुपर	पटाविजैपुरा	2119-मि0	0.405	5-1-नवीन	शिक्षा विभाग को
				ग्राम समाज			परती	प्राथमिक विद्यालय पठा
				पटाविजैपुरा				(अंग्रेजी माध्यम) के
								भवन निर्माण हेतु।

#### 26 सितम्बर, 2020 ई0

सं० 3016 / आठ-एल0ए०सी०-पुर्न० (2020-21)—शासनादेश संख्या 258 / रा०-1 / 16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन्

## अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	जाधकारा  5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	दौलता	425 / 11	0.160	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				ककड़ारी				प्रदेश को मऊ ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 3017/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा०-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	तरगुवां	1014	0.162	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				तरगुवां				प्रदेश को कड़ेसराकलां
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 3018/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन्

## अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	मुकटौरा	252/2	0.162	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				मुकटौरा				प्रदेश को मऊ ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 3019/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	बांसी	रायपुर	857-मि0	0.162	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				रायपुर				प्रदेश को लागौन ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं० ३०२० / आठ-एल०ए०सी०-पुर्न० (२०२०-२१)—शासनादेश संख्या २५८ / रा०-१ / १६(१)-७३, दिनांक ०५ मार्च, १९७४ का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, सन्

## अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	बानुपर	भावनी	721	0.250	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				भावनी				प्रदेश को चन्दावली ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

30 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 3049/आट-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी			-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	बालाबेहट	पटरा	43	0.388	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				सिमरधा				प्रदेश को धौर्रा-बालाबेहट
								ग्राम समूह पाइप
								पेयजल योजना हेतु।

सं0 3057/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन्

## अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	बानपुर	बछरावनी	177	0.160	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				बछरावनी				प्रदेश को चन्दावली ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 3058/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

<u></u> 큙0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	सुनौरी	2210	0.250	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				सुनौरी				प्रदेश को बदनुपर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 3059/आठ-एल0ए०सी०-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55

द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

## अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	बांसी	बाजनौ	334/3	0.250	६-४-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज				जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				जमौरामाफी				प्रदेश को लागौन ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 3060/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	बांसी	बुड़ेरा	167/8	0.160	5-3-ड़,	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			बंजर	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				बादरौन				प्रदेश को मऊ ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 3061/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

		4
अ	+	चा
-		·

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	चन्दावली	318-मि0	0.809	5-1-नवीन	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज			परती	जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				चन्दावली				प्रदेश को चंदावली ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

सं0 3062/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, लिलतपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण-प्रयोजन जिसके
सं0				सभा /	संख्या		श्रेणी /	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
				स्थानीय			प्रकृति	की जा रही है
				प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	भुजऊपुरा	179	0.134	6-4-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण
				ग्राम समाज	155-मि0	0.026		जलापूर्ति विभाग, उत्तर
				धनगौल	योग	0.160		प्रदेश को चन्दावली ग्राम
								समूह पाइप पेयजल
								योजना हेतु।

अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर।

### बाँदा के जिलाधिकारी की आजायें

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 12(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्तयों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, २०16 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बॉदा	बबेरू	जरोहरा	जरोहरा	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 290	415	0.7180 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 13(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, २०16 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	भदवारी	भदवारी	5-1 नवीन परती खाता संख्या 399	416	0.158 में से 0.065	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिश्रन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 14(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, २०16 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	सतन्याव	सतन्याव	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 820	505-मि0	0.0810 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 15(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, २०16 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसुची

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	कोरारी	कोरारी	5-1 नवीन परती खाता संख्या 294	424	0.175 में से 0.125	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 16(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०१२) की धारा ५९ की उपधारा (४) के खण्ड १ (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या ७४४ / एक-१-बी(५) / २०१६, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०१६ के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ६८७ / एक-१-२०२०(५) / २०१६, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते

हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

		•
अ	नस	चा
٠.		

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	पवइया	पवइया	5-1 बंजर खाता संख्या 1414	910	0.934 में से 0.070	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिश्रन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 17(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, २०16 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बाँदा	खौड़ा	खौड़ा	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 407	658-मि0 658-मि0	0.140 0.229 0.369 详 社 0.345	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 18(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०१२) की धारा ५९ की उपधारा (4) के खण्ड १ (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या ७४४ / एक-१-बी(५) / २०१६, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०१६ के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ६८७ / एक-१-२०२०(५) / २०१६, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

			_0_
अ	न	स	चा
٧,	ᆚ	٠,	

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	मुड़वारा बॉगर	मुड़वारा बॉगर	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 531	1484	1.8290 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिश्रन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 19(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्तयों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, २०16 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	पेस्टा	पेस्टा	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 743	913	0.786 में से 0.070	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 20(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

अ	नर	चा
٠.	.4.	, -ιι

क्र0	जिला	तहसील /	ग्राम	ग्राम सभा	खाता	गाटा	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये
सं0		परगना			संख्या / भूमि	संख्या		भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
					की श्रेणी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	_
1	बाँदा	पैलानी	नरी बॉगर	नरी	6-2 बीहड़	149-ख	1.6760	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता
					खाता संख्या		में से	मिशन (नमामि गंगे तथा
					1161		0.0625	ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
								उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल योजना
								के निर्माण हेतु।

सं0 21(5)/12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्तयों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक ०६ जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बॉदा	बबेरू	अछाह	अछाह	5-1 नवीन परती खाता संख्या 436	434	0.2670 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 22(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

			_0_
अ	न	स	चा
٧,	ᆚ	٠,	

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	पतवन	पतवन	6-2 पेय नलकूप घेरा खाता संख्या 1665	2242	0.146	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 23(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्तयों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, २०16 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील /	ग्राम	ग्राम सभा	खाता	गाटा	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये
सं0		परगना			संख्या / भूमि	संख्या		भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
					की श्रेणी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बाँदा	मटौंध	मटौंध	5-1 नवीन	5803	0.1600	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता
			ग्रामीण	ग्रामीण	परती खाता			मिशन (नमामि गंगे तथा
					संख्या ३२२०			ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
								उ०प्र० को मटौंध ग्रामीण
								पाइप पेयजल योजना के
								निर्माण हेतु।

सं0 24(5) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

अ	नर	चा
٠.	.4.	, -ιι

					<b>0</b> 5.			
क्र0	जिला	तहसील /	ग्राम	ग्राम सभा	खाता	गाटा	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये
सं0		परगना			संख्या / भूमि	संख्या		भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
					की श्रेणी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बाँदा	हटेटीपुरवा	हटेटीपुरवा	5-3-ङ बंजर	1481 / 1	1.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता
					खाता संख्या			मिशन (नमामि गंगे तथा
					725			ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
								उ०प्र0 को अमलीकौर ग्राम
								समूह पाइप पेयजल योजना
								के निर्माण हेतु।

सं0 198(6) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या ०८, सन् २०12) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक ०३ जून, २०16 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-७ में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक ०३ जून, २०16 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील /	ग्राम	ग्राम सभा	खाता	गाटा	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये
सं0		परगना			संख्या / भूमि	संख्या		भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
					की श्रेणी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	औगासी	औगासी	6-2 अस्पताल	1334	0.328	पशु सेवा केन्द्र औगासी की
			बॉगर		खाता संख्या		में से	स्थापना हेतु।
					738		0.150	

सं0 199(6) / 12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744 / एक-1-बी(5) / 2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020(5) / 2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

			_
अ	न	स	711
v		٠,	<b>~11</b>

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बाँदा	हटेटीपुरवा	हटेटीपुरवा	5-3-ङ बंजर	1481 / 1	1.0000	नगरपालिका परिषद्, बाँदा
					खाता संख्या			को मैटेरियल रिकवरी
					725			फैसिलिटी एवं ठोस अपशिष्ट
								प्रबन्धन प्लॉट निर्माण हेतु।

आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बाँदा।

# झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

23 अक्टूबर, 2020 ई0

सं० 912/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ०प्र० सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम रमपुरा, मवई, बमनुवाँ, हाटी, खिरिया, पिपरा, खोह, सेमरी, बंका पहाड़ी, जौरी, कल्यानपुरा (रावतपुरा), धमना खुर्द एवं उजयान, तहसील टहरौली के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
•						हेक्टेयर		
1	झाँसी	टहरौली	टहरौली	रमपुरा	161-मि0	0.162	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल एवं
2	झाँसी	टहरौली	टहरौली	पिपरा	534-मि0	0.162	श्रेणी-5-3 क बंजर	स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा
3	झाँसी	टहरौली	टहरौली	मवई	390 / 4	0.161	श्रेणी-6-4 ऊसर	ग्रामीण जलापूर्ति
4	झाँसी	टहरौली	टहरौली	बमनुवॉ	634-मि0	0.121	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	विभाग, उ०प्र०)
5	झाँसी	टहरौली	टहरौली	हाटी	899 / 8-मि0	0.162	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	(नि:शुल्क)
6	झाँसी	टहरौली	टहरौली	खिरिया	166-मि0	0.202	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
7	झाँसी	टहरौली	टहरौली	खोह	65-मि0	0.260	श्रेणी-5-3 क् बंजर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
8	झाँसी	टहरौली	टहरौली	सेमरी	1159-मि0	0.016	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल एवं
9	झाँसी	टहरौली	टहरौली	बंका पहाड़ी	1152-मि0	0.081	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
10	झाँसी	टहरौली	टहरौली	जौरी	141	0.154	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	विभाग, उ०प्र०)
11	झाँसी	टहरौली	टहरौली	कल्यानपुरा (रावतपुरा)	37	0.158	श्रेणी-5-1 नवीन परती	(नि:शुल्क)
12	झाँसी	टहरौली	टहरौली	धमनाखुर्द	359-मि0	0.250	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
13	झाँसी	टहरौली	टहरौली	उजयान	634-मि0	0.080	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
					588	0.182		

सं0 913/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ०प्र० सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम बिरगुवा, सेसा, सिया, निवी एवं पसैया, तहसील मोंठ के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

		^
अ•	नस	चा

<u>क्</u> र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	मोंठ	मोंठ	निवी	137 / 2-मि0	0.090	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल एवं
2	झाँसी	मोंठ	मोंठ	बिरगुवॉ	144-मि0	0.162	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	स्वच्छता मिशन
3	झाँसी	मोंठ	मोंठ	सेसा	558	0.073	श्रेणी-5-1 न0 परती	(नमामि गंगे तथा
4	झाँसी	मोंठ	मोंठ	सिया	805-मि0	0.090	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	ग्रामीण जलापूर्ति
5	झाँसी	मोंठ	मोंठ	पसैया	275-मि0	0.090	श्रेणी-5-1 न० परती	विभाग, उ०प्र०) (निःशुल्क)

सं0 914/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ०प्र० सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम सेवारा, बेरवई, बंगराधवा,

कुआगॉव, लुहारी, चितावद, सप्तवारा, धबाकर, उल्दन, बम्हौरी, घुराट एवं मगरवारा, तहसील मऊरानीपुर के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

					अनुसूची			
क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की	विवरण (प्रयोजन
					संख्या		श्रेणी / प्रकृति	जिसके लिये
								भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	सेवारा	43-मि0	0.101	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल
2	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	बेरवई	408-मि0	0.134	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	एवं स्वच्छता
3	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	बंगराधवा	97-मि0	0.202	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	मिशन (नमामि
4	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	कुआगॉव	320	0.356	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	गंगे तथा ग्रामीण
5	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	लुहारी	197-मि0	0.150	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	जलापूर्ति विभाग, उ०प्र०)
6	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	चितावद	3	0.113	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	(निःशुल्क)
7	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	सप्तवारा	220-मि0	0.284	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	( ' 3 ' ')
8	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	धबाकर	1413-मि0	0.134	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
9	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	उल्दन	399-मि0	0.180	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
10	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	बम्हौरी	424-मि0	0.161	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
11	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	घुराट	1527-मि0	0.200	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
12	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	मगरवारा	595-मि0	0.250	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	

सं० 915/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ०प्र० सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम तैदोल एवं गढ़मऊ, तहसील झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि
								पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	तैदोल	2389	0.267	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल एवं
2	झाँसी	झाँसी	झाँसी	गढ़मऊ	1308	0.231	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	स्वच्छता मिशन
								(नमामि गंगे तथा
								ग्रामीण जलापूर्ति
								विभाग, उ०प्र०)
								(नि:शुल्क)

सं० 916/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ०प्र० सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम कुरैठा, हरदुवा, जलालपुरा, अङ्जरा, परसुवा, रौतानपुरा, मारकुवां, बिरौना, धनौरा एवनी, गढ़वई एवं डुमरई, तहसील गरौठा के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ:

#### अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	गरौटा	गरौटा	कुरैठा	1392	0.250	श्रेणी-6-4 बेहड़	राज्य पेयजल
2	झाँसी	गरौठा	गरौठा	हरदुवा	23-ख	0.231	श्रेणी-6-4 बीघड़	एवं स्वच्छता
3	झाँसी	गरौठा	गरौठा	जलालपुरा	250-मि0	0.160	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण
4	झाँसी	गरौटा	गरौठा	अड़जरा	185-क	0.308	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	जलापूर्ति विभाग,
5	झाँसी	गरौठा	गरौठा	परसुवा	1490	0.073	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	ਚ0प्र0)
					1491-ख	0.093		(नि:शुल्क)
6	झाँसी	गरौठा	गरौठा	रौतानपुरा	22-ग-मि0	0.252	श्रेणी-6-4 बीहड़	
7	झाँसी	गरौठा	गरौटा	मारकुवां	241-मि0	0.205	श्रेणी-5-(1) न0 परती	
8	झाँसी	गरौठा	गरौठा	बिरौना	84	0.065	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
					86	0.065		
					88-मि0	0.030		
9	झाँसी	गरौठा	गरौठा	धनौरा	3653-मि0	0.250	श्रेणी-6-4 बीहड़	
10	झाँसी	गरौठा	गरौठा	एवनी	1166-मि0	0.200	श्रेणी-5-3 ड बंजर	
11	झाँसी	गरौठा	गरौटा	गढ़वई	341-मि0	0.250	श्रेणी-5-(1) न0 परती	
12	झाँसी	गरौठा	गरौठा	डुमरई	563-ख-मि0	0.162	श्रेणी-6-4 बेहड़	

सं0 917/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)-2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी,

जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बामौर, तहसील गरौठा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ :

## अनुसूची

郊0	जिला	तहसील व	गांव	गांव <sup>:</sup> श्रेर्ण	सभा की ऐर ो परिवर्तन	प्ती भूमि जिसका किया जाता है			भूमि जिससे श्रेणी या जाता है
		परगना		गाटा संख्या	क्षेत्रफल श्रेणी		गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	गरौटा	बामौर (ग्राम पंचायत बामौर)	434	1.712 में से 0.146	श्रेणी-5(3) ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (चारागाह) के स्थान पर श्रेणी- 5(3) ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	(176) ग्राम ननौली (ग्राम पंचायत बामौर)	0.146	श्रेणी-5(3) ड अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-5(3) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (खलिहान)

आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झांसी।

# जालौन स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

21 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 1722 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	सिकरी रहमानपुर	333-क	0.310 में से रकबा 0.160	5-1 / कृषि योग्य भूमि नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिश्रन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम सिकरी रहमानपुर पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 4,07,650.00 (मु० चार लाख सात हजार छः सौ पचास रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1723 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

<u></u> 큙0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा	क्षेत्रफल		विवरण (प्रयोजन, जिसके
सं0					संख्या		प्रकृति	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	दशहरी	185	0.101	5-1 / कृषि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता
							C.	मिशन (नमामि गंगे तथा
							नई परती	ग्रामीण जलापूर्ति विभाग),
							(परतीजदीद)	उ०प्र० ग्राम दशहरी नलकूप
							नवीन परती	पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,09,181.00 (मु० एक लाख नौ हजार एक सौ इक्यासी रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1724 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	सुजानपुर	20	हेक्टेयर 0.344 में से	जो श्रेणी 5- 1 / कृषि योग्य	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा
						0.160	17 पृगंप पांच्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम सुजानपुर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,66,400.00 (मु० एक लाख छियासठ हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1725 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	जीतामउ मु0	209/1	3.238 में से 0.160	6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम जीतामउ मु० पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 10,00,800.00 (मु० दस लाख आठ सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1726 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनसची	ſ
OLIVE	1

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालीन	कालपी	कालपी	खेरई	295	0.789 में से 0.160	5-1 / कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम खैरई नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 2,16,000.00 (मु० दो लाख सोलह हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1727 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

	अनुसूची										
<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/	विवरण (प्रयोजन, जिसके			
सं0					संख्या		प्रकृति	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा			
								रही है)।			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						हेक्टेयर					
1	जालौन	कालपी	कालपी	उकरूवा	28/2	0.160	5-1 / कृषि योग्य	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता			
							भूमि- नई परती	मिशन (नमामि गंगे तथा			
							(परतीजदीद)	ग्रामीण जलापूर्ति विभाग),			
							नवीन परती	उ०प्र० ग्राम उकरूवा			
								नलकूप पाइप पेयजल			
								योजना हेतु।			

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,39,200.00 (मु० एक लाख उनतालीस हजार दो सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1728 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	कुटरा मुस्तकिल	122/1	1.177 में से 0.160	6-4 / बेहड़ भूमि जो अन्य कारणों से अकृषित हो	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम कुटरा मुस्तकिल नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,44,000.00 (मु० एक लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1729 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

		~
.घ	नग्र	ाना
VI	. I 🗸	LЧI

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	लमसर	63	2.732 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/ कृषि योग्य भूमि- नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम लमसर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 2,48,000.00 (मु० दो लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1730 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

	अनुसूची											
क्र0 संव	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/	विवरण (प्रयोजन, जिसके				
सं0					संख्या		प्रकृति	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						हेक्टेयर						
1	जालौन	कालपी	कालपी	उरकराकला	1656	0.101	•	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता				
					व	व		मिशन (नमामि गंगे तथा				
					1657	0.032	(परतीजदीद)	ग्रामीण जलापूर्ति विभाग),				
						कुल रकवा	नवीन परती	उ०प्र० ग्राम उरकराकला नलकुप पाइप पेयजल				
						0.133		नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।				

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,95,510.00 (मु० एक लाख पंचानबे हजार पांच सौ दस रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1731 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

			_0
अ	न	ч	चा

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	सुनहेटा	710	1.137 में से 0.160	6-4 / बेहड़ जो अन्य कारणों से अकृषित हो	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम सुनहेटा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,05,600.00 (मु० एक लाख पांच हजार छः सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1732 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

			•	١.
21	Ŧ	ग	71	т
v	١.	7.1	ч	1
	- 2	) С	`	

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	सुरहटी	363	0.101		राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम सुरहटी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 95,700.00 (मु० पंचानबे हजार सात सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1733 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

	अनुसूची											
क्र0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/	विवरण (प्रयोजन, जिसके				
सं0					संख्या		प्रकृति	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा				
								रही है)।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						हेक्टेयर						
1	जालौन	कालपी	कालपी	ताहरपुर	131	0.142	5-3-ड / अन्य	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता				
							कृषि योग्य बंजर	मिशन (नमामि गंगे तथा				
							भूमि	ग्रामीण जलापूर्ति विभाग),				
								उ०प्र० ग्राम ताहरपुर नलकूप				
								पाइप पेयजल योजना हेतु।				

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,47,680.00 (मु० एक लाख सैतालीस हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1734 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	बोहदपुरा	722 / 1	रकबा 0.190 में से रकबा 0.108	5-3-ड / अन्य कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना बोहदपुरा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 8,91,000.00 (मु० आठ लाख इक्यानवे हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1735 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अ	नस	ची
V.	. I / I	·МI

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	मवई मौखरी	37/1	0.090	•	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना अटा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,24,740.00 (मु० एक लाख चौबीस हजार सात सौ चालीस रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1736 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अ	नर	न चा
٠.	.4.	ν

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	सला	365-क	10.178 में से रकबा 3.000	जो श्रेणी 6- 4 / भूमि जो अन्य कारणों से अकृषक है। खेड़ा आबादी	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० ग्राम सला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु ग्राम सला।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 43,50,000.00 (मु० तैतालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1737 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रितिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कोंच	कोंच	विरगुवां बुजुर्ग	269-मि0	हेक्टेयर 0.963 में से 0.160	5-1 / कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना विरगुवां बुजुर्ग।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 2,40,000.00 (मु० दो लाख चालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1738 / 8-डी०एल०आर०सी०—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शिक्त का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा० मन्नान अख्तर, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

<u>क्र</u> 0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/	विवरण (प्रयोजन, जिसके
सं0					संख्या		प्रकृति	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा
								रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	मदनेपुर	206	0.182	5-1 / कृषि योग्य	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता
				जालौन	सा0आ0	में से	भूमि-नई परती	मिशन (नमामि गंगे तथा
						0.090	(परतीजदीद)	ग्रामीण जलापूर्ति विभाग),
							नवीन परती	उ०प्र० के अन्तर्गत कोटरा
								मुस्त0 ग्राम समूह पेयजल
								योजना अटा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,14,300.00 (मु० एक लाख चौदह हजार तीन सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1739 / 8-डी०एल0आर0सी0—शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	तिरावली	20	0.259 में से 0.160	6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो। बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ०प्र० के अन्तर्गत कोटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना तिरावली।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,91,590.00 (मु० एक लाख इक्यानवे हजार पांच सौ नब्बे रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

डा० मन्नान अख्तर, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।

# वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

13 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 6181/सात-भू०सु०/2020-शासनादेश संख्या 68/3-2(6)79 रा०-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश संख्या 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2017 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार

अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकर में लेता हूं। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 7/8 में उल्लिखित गाटा संख्या 341-मि0, रकबा 0.280 हे0, साइबर क्राइम, थाना-भिखारीपुर के निर्माण हेतु, गृह (पुलिस) विभाग को हस्तगत कराया जाय:

				Δ
अनुसूचा	अ	न्र	पुर	ग्र

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट संख्या / गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	राजातालाब	कसवार	भिखारीपुर	341-मि0	हेक्टेयर 0.280	गृह (पुलिस) विभाग, साइबर
			राजा				क्राइम, थाना-भिखारीपुर के निर्माण हेतु।

### 19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 6199 / सात-भू०सु0-2020—जनपद वाराणसी में के०िर०पु० बल की 95 बटालियन मुख्यालय की स्थापना के लिये क्रय की जा रही 12.592 हे0 भूमि के साथ संलग्न ग्राम सभा की 0.387 हे0 भूमि में से शेष गाटा सं0 1028 के रकबा 0.030 हे0 (रास्ता) जो ग्राम सभा की ऐसी भूमि जो बाहर से शुरू होकर संस्था के बाउण्ड्रीवाल के अन्दर समाप्त होती है, का विनिमय किये जाने का प्रस्ताव उप जिलाधिकारी, पिण्डरा, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उप जिलाधिकारी, पिण्डरा, वाराणसी की आख्या दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के अनुसार ग्राम थाना, परगना कोलआसला, तहसील पिण्डरा, वाराणसी में के०रि०पु० बल के 95 बटालियन मुख्यालय की स्थापना से प्रभावित ग्राम सभा की भूमि गाटा सं0 1028 जो अभिलेख खतौनी में खाता सं0 882 पर रास्ता के नाम से अंकित है के कुल रकबा 0.259 हे0 में से 0.030 हे0 रकबा प्रभावित है। प्रभावित गाटा सं0 1028 रकबा 0.030 हे0 भूमि के बदले के०रि०पु० बल के नाम भूमि 981 में से रकबा 0.021 हे0 व गाटा सं0 983 में से रकबा 0.009 हे0 से विनिमय किया जाना है। प्रभावित व प्रस्तावित भूमि की मालियत रू0 31,50,000.00 है, जिसके मूल्यांकन में कोई भिन्नता नहीं है।

शासनादेश संख्या 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित राजस्व अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या 688 / एक-1-2020-20(5) / 2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियों और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहां राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिये तथा जहां वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिये अपेक्षित हों, रुपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रुपये 40 लाख से अधिक वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह भी उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 से आच्छादित आरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन / पुनर्ग्रहण / विनिमय की कार्यवाही नितांत अपवादात्मक एवं अपिरहार्य परिस्थितियों में ही की जायेगी और यदि धारा 77 से आच्छादित भूमि का श्रेणी परिवर्तन / पुनर्ग्रहण किया जाता है, तो उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित की जायेगी या धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय के माध्यम से की जायेगी। आरिक्षत श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरिक्षत किये जाने के लिये या विनिमय किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि की स्थिति लोक उपयोगिता और उपयुक्ता सम्बन्धित कलेक्टर एवं मण्डलायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शासनादेश के आलोक में उप जिलाधिकारी पिण्डरा, वाराणसी द्वारा विनिमय हेतु प्रस्तावित आख्या दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के अनुसार ग्राम थाना परगना कोलअसला, तहसील पिण्डरा, वाराणसी में स्थित ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि गाटा 1028 रकबा 0.030 हे0 जिसका मूल्यांकन रु० 3,15,000.00 है, के बदले के०रि०पु० बल के नाम गाटा सं0 981 में से रकबा 0.021 हे0 व गाटा सं0 983 में रकबा 0.009 हे0 कुल 02 गाटा रकबा 0.030 हे0 जिसका मूल्यांकन रु० 3,15,000.00 है। जिसका विवरण निम्नवत् है:

## अनुसूची

ग्राम थाना, परगना कोलअसला, तहसील पिण्डरा वाराणसी में के०रि०पु० बल द्वारा लिये जाने वाले भूमि का विवरण / मूल्यांकन						ग्राम थाना, परगना कोलअसला, तहसील पिण्डरा, वाराणसी में स्थित भूमि के०रि०पु० बल के नाम की भूमि को ग्राम सभा में दर्ज किये जाने का विवरण/मूल्यांकन			
क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	रकबा	मूल्यांकन रु० में	क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	रकबा	मूल्यांकन
			हेक्टेयर					हेक्टेयर	रु0
1	थाना	1028	0.030	3,15,000	1	थाना	981,983 कुल 02 गाटा	0.030	3,15,000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्राम थाना, परगना कोलअसला, तहसील पिण्डरा, वाराणसी में स्थित के०रि०पु० बल की ग्राम थाना, परगना कोलअसला, तहसील पिण्डरा, वाराणसी में स्थित भूमि व ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि का मूल्यांकन के आधार पर समान है जो समतुल्य मूल्य की भूमि है, जिसका विनिमय किये जाने योग्य है। जहां तक लोक उपयोगिता एवं उपयुक्तता का प्रश्न है, उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि विनिमय होने के पश्चात् सार्वजनिक रास्ता जो की के०रि०पु० बल की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर समाप्त होने से बन्द हो गया था, वह खुल जायेगा।

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्राविधानों के आलोक में उप जिलाधिकारी, पिण्डरा, वाराणसी की आख्यानुसार प्रकरण में ग्राम सभा थाना की रास्ते की भूमि के बदले के०रि०पु० बल के उसी ग्राम में स्थित समतुल्य भूमि से प्रस्तावित विनिमय किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी।

# कार्यालय उपसम्भागीय परिवहन अधिकारी, जनपद बदायूं

07 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 6848/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर0—74/8010 बुलैरो, जिसका चेसिस नं0 MA1PS2GBK92G98541 एवं इन्जन नं0 GB94G76950, विनिर्माता महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, मॉडल 2011, नेक्सू लाल पुत्र श्री गोविन्दराम, निवासी ग्राम-कटरा सआदतगंज, दातागंज, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 06 फरवरी, 2013 को स्वामित्व हस्तान्तरण किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 8010 बुलैरो की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में नेक्सू लाल पुत्र श्री गोविन्दराम, निवासी ग्राम कटरा सआदतगंज, दातागंज, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6767 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6788 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु नेक्सू लाल पुत्र श्री गोविन्दराम,

निवासी ग्राम कटरा सआदतगंज, दातागंज, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी नेक्सू लाल पुत्र श्री गोविन्दराम, निवासी ग्राम कटरा सआदतगंज, दातागंज, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर0—74/8010 बुलैरो का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6849/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर0-74/5822 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT426101A0H14100 एवं इन्जन नं0 01G62902632, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, नूर मोहम्मद पुत्र श्री लल्ला, निवासी आरिफपुर नवादा, सिविल लाइन, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 28 मार्च, 2018 को स्वामित्व हस्तान्तरण किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 5822 ट्रक की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में नूर मोहम्मद पुत्र श्री लल्ला, निवासी आरिफपुर नवादा, सिविल लाइन, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6762 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6783 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, एवं पत्र सं० 6812 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु नूर मोहम्मद पुत्र श्री लल्ला, निवासी आरिफपुर नवादा, सिविल लाइन, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी नूर मोहम्मद पुत्र श्री लल्ला, निवासी आरिफपुर नवादा, सिविल लाइन, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर0 74/5822 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6850 / सा0प्रशा0 / पंजीयन निरस्तीकरण / 2020—वाहन संख्या एच0आर0-74 / 5152 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT426101A0E09900 एवं इन्जन नं0 01D62872139, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, अय्यूब पुत्र श्री भूरे, निवासी C/o सुनील कुमार, आरिफपुर नवादा, सिविल लाइन, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 5152 ट्रक की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में अय्यूब पुत्र श्री भूरे, निवासी C/o सुनील कुमार, आरिफपुर नवादा, सिविल लाइन, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6763 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6784 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक के स्वर्ण सं० 6818 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु अय्यूब

पुत्र श्री भूरे, निवासी C/o सुनील कुमार, आरिफपुर नवादा, सिविल लाइन, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी अय्यूब पुत्र श्री भूरे, निवासी C/o सुनील कुमार, आरिफपुर नवादा, सिविल लाइन, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर0 74/5152 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6851/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर0-74/4870 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT426101A0E09896 एवं इन्जन नं0 D62872166, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, श्री संजय कुमार पुत्र श्री मोना सिंह, निवासी, C/o Taharuddin खेड़ा नवादा, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 4870 ट्रक की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार पुत्र श्री मोना सिंह, निवासी, C/o Taharuddin खेड़ा नवादा, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6760 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6781 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र सं० 6819 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु श्री संजय कुमार पुत्र श्री मोना सिंह, निवासी, C/o Taharuddin खेड़ा नवादा, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री संजय कुमार पुत्र श्री मोना सिंह, निवासी, C/o Taharuddin खेड़ा नवादा, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर0 74/4870 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6852/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर0—74/3335 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT426101AB02397 एवं इन्जन नं0 01A62835681, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, शोएब पुत्र श्री असगर, निवासी खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को स्वामित्व हस्तान्तरण किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 3335 ट्रक की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के

सम्बन्ध में शोएब पुत्र श्री असगर, निवासी खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6764/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6785/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र सं० 6810/सा0प्रशा0/ टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु शोएब पुत्र श्री असगर, निवासी खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी शोएब पुत्र श्री असगर, निवासी खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर0 74/3335 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6853/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर0-74/3301 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT426101A0B02392 एवं इन्जन नं0 0A62836007, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, बाबू हुसैन पुत्र श्री मुख्तार हुसैन, निवासी आरिफपुर नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 28 मार्च, 2018 को स्वामित्व हस्तान्तरण किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 3301 ट्रक की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में बाबू हुसैन पुत्र श्री मुख्तार हुसैन, निवासी आरिफपुर नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6765 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6786 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र सं० 6817 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु बाबू हुसैन पुत्र श्री मुख्तार हुसैन, निवासी आरिफपुर नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी बाबू हुसैन पुत्र श्री मुख्तार हुसैन, निवासी आरिफपुर नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन०सी० शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच०आर० 74/3301 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6854/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर0-74/3001 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 T426101A0A01212 एवं इन्जन नं0 01A62830476, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, अहाद अहमद पुत्र श्री मीरा सैय्यद अहमद, निवासी खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 21 जनवरी, 2018 को स्वामित्व हस्तान्तरण किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 3001 ट्रक की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में अहाद अहमद पुत्र श्री मीरा सैय्यद अहमद, निवासी खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6759 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6780 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र सं० 6816 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु अहाद अहमद पुत्र श्री मीरा सैय्यद अहमद, निवासी खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी अहाद अहमद पुत्र श्री मीरा सैय्यद अहमद, निवासी खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर0 74/3001 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6855/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर0-74/2999 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 R426101A0A01209 एवं इन्जन नं0 0162830459, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, फिरोज खान पुत्र श्री अब्दुल अजीज, निवासी ग्राम खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को स्वामित्व हस्तान्तरण किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हिरयाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 2999 ट्रक की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में फिरोज खान पुत्र श्री अब्दुल अजीज, निवासी ग्राम खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6758 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6779 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र सं० 6815 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु फिरोज खान पुत्र श्री अब्दुल अजीज, निवासी ग्राम खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी फिरोज खान पुत्र श्री अब्दुल अजीज, निवासी ग्राम खेड़ा नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन0सी० शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर0 74/2999 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6856 / सा0प्रशा0 / पंजीयन निरस्तीकरण / 2020—वाहन संख्या एच0आर0-74 / 2705 (यू0पी0-24 / T-5781 नया पंजीयन चिन्ह) ट्रक, जिसका चेसिस नं0 T42610190P21642 एवं इन्जन नं0 90M62816723, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, वसीम पुत्र श्री फारूख, निवासी आरिफपुर नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को स्वामित्व हस्तान्तरण किया गया था। संज्ञान में आया कि उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 नूह, हरियाणा से बदायूं के लिये जारी नहीं की गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं के द्वारा पत्रांक 6755 / एन०ओ०सी० सत्यापन / 2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र सं० 1464, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन सं० एच०आर० 74 / 2705 (यू०पी०-24 / T-5781 नया पंजीयन चिन्ह) ट्रक की एन०ओ०सी० इस कार्यालय के पंजीकरण अनुसार जारी नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में वसीम पुत्र श्री फारूख, निवासी आरिफपुर नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं को इस कार्यालय के पत्र सं० 6761 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020, पत्र सं० 6782 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र सं० 6814 / सा०प्रशा० / टी०आर० / नोटिस / 2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु वसीम पुत्र श्री फारूख, निवासी आरिफपुर नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी वसीम पुत्र श्री फारूख, निवासी आरिफपुर नवादा, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन कराया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी बदायूं/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर0 74/2705 (यू0पी0-24/T-5781 नया पंजीयन चिन्ह) ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

एन०सी० शर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन), बदायं।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

## प्रयागराज, शनिवार, ५ दिसम्बर, २०२० ई० (अग्रहायण १४, १९४२ शक संवत्)

#### भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

#### खण्ड-घ

#### जिला पंचायत

28 अक्टूबर, 2020 ई0

सं० 142 / 23-एल०बी०ए०-4 (2018-19)—आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी की विज्ञप्ति संख्या 2977-78 / 23-एल०बी०ए०-58 (91-92), दिनांक 18 अप्रैल, 1998 एवं संख्या 77-78 / 23-एल०बी०ए०-58 (91-92), दिनांक 08 अक्टूबर, 2001, संख्या 4445-46 / 23-एल०बी०ए०-58 (91-92), दिनांक 07 जून, 2003, पत्र संख्या 2967 / 23-एल०बी०ए०-58 (91-92), दिनांक 08 मई, 2007 तथा पत्र संख्या 3383-84 / 23-एल०बी०ए०-58 (91-92), दिनांक 06 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रख्यापित जनपद जालौन के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक भूमि अथवा निजी भूमि पर साप्ताहिक अथवा प्रतिदिन लगने वाले बाजारों को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी तहबाजारी उपविधियों में जिला पंचायत, जालौन द्वारा उपविधि संख्या 14 के अनुसार प्रभावी दर सूची की मद संख्या 01 लगायत 06 की दरों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। एतद्द्वारा उ०प्र० जिला पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित उ०प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के अधीन संशोधन को पुष्टिकृत करते हुये, संशोधित सूची को नीचे इस प्रयोजन से प्रकाशित किया जाता है कि संशोधित दरें गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी:

#### संशोधन

क्र0सं0	मद संख्या	प्रचलित दर	संशोधित दर
		₹0	₹0
1	नौकाघाट/नदी तल व नालों से प्राप्त होने वाली बालू भरने का छोटा ट्रक/डम्फर	100.00 प्रति ट्रक	200.00 प्रति ट्रक
2	नौकाघाट / नदी तल व नालों से प्राप्त होने वाली बालू भरने का मैटाडोर / ट्रैक्टर प्रति ट्राली	50.00 प्रति मैटाडोर/ ट्रैक्टर प्रति ट्राली	100.00 प्रति मैटाडोर / ट्रैक्टर प्रति ट्राली

क्र0सं0	मद संख्या	प्रचलित दर	संशोधित दर	
		₹0	₹0	
3	नौकाघाट / नदी तल व नालों से प्राप्त होने वाली बालू भरने का बड़ा ट्रक / डम्फर (06 टायर से ऊपर)	150.00 प्रति ट्रक / डम्फर	300.00 प्रति ट्रक/डम्फर	
4	नौकाघाट / नदी तल व नालों से प्राप्त होने वाली बालू भरने का बड़ा ट्रक / डम्फर (10 टायर से ऊपर)	200.00 प्रति ट्रक / डम्फर	400.00 प्रति ट्रक / डम्फर	
5	गिट्टी / पत्थर बोल्डर एवं पहाड़ों से क्षरण होने वाली मोरम का भरा बड़ा ट्रक / डम्फर (06 टायर से ऊपर)	150.00 प्रति ट्रक / डम्फर	300.00 प्रति ट्रक / डम्फर	
6	गिट्टी / पत्थर बोल्डर एवं पहाड़ों से क्षरण होने वाली मोरम का भरा बड़ा ट्रक / डम्फर (10 टायर से ऊपर)	200.00 प्रति ट्रक / डम्फर	400.00 प्रति ट्रक / डम्फर	

14(अ) इस तहबाजारी की वसूली हेतु ठेके की स्थिति में अपर मुख्याधिकारी की स्वीकृति से वसूली हेतु केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों से गुजरने वाले वाहनों से उक्त शुल्क देय होगा, किन्तु इस प्रयोजन से जिला पंचायत द्वारा कोई बैरियर नहीं लगाया जायेगा।

> सुभाष चन्द शर्मा, आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

## प्रयागराज, शनिवार, ५ दिसम्बर, २०२० ई० (अग्रहायण १४, १९४२ शक संवत्)

#### भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां। भारत निर्वाचन आयोग

#### आदेश

सं० 76 / उ०प्र०-वि०स० / 79 / 2017—**यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई / प्रे०नो० / 1 / 2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री यतेन्द्र सिंह अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री यतेन्द्र सिंह को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ०प्र0-वि0स0/79/भा0नि0आ0/नोटिस/टेरी0/उ०अनु0-III-उ०प्र0/2017 जारी किया गया था :

- (1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; और
- (2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री यतेन्द्र सिंह को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री यतेन्द्र सिंह को दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री यतेन्द्र सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री यतेन्द्र सिंह को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/ उ०प्र०-वि०स०/७१/भा०नि०आ०/पत्र/टेरी०/उ०अनु०-III-उ०प्र०/2017, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उनकी पत्नी श्रीमती पायल दिनांक 18 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री यतेन्द्र सिंह द्वारा उक्त किमयों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस / पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री यतेन्द्र सिंह विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि—

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा
  - (ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'':

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री यतेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट बर्द्ववारी मुरसान, हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरहित होंगे।

#### **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

	18 <sup>th</sup> August, 2020
New Delhi, dated the	
	Shravana 27, <sup>th</sup> 1942 (Saka).

#### **ORDER**

**No.** 76/UP-LA/79/2017–WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04<sup>th</sup> January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11<sup>th</sup> March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10<sup>th</sup> April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12<sup>th</sup> April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Yatendra Singh, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18<sup>th</sup> October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Yatendra Singh, for the following defects in accounts of his election expenses:

- (i) Bill vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure; and
- (ii) Bank Statement has not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Yatendra Singh, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Shri Yatendra Singh, on 19<sup>th</sup> November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7<sup>th</sup> August, 2019 that Shri Yatendra Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 01<sup>st</sup> October, 2019 which was served to his wife Smt. Paayal on 18<sup>th</sup> March, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 07<sup>th</sup> August, 2020 submitted by the District Election Officer, to the Commission Shri Yatendra Singh, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Yatendra Singh has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

- "If the Election Commission is satisfied that a person-
- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

Now Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Yatendra Singh, Resident of Village & Post Bardhavari Mursan, Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order, ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secretary, Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, ५ दिसम्बर, २०२० ई० (अग्रहायण १४, १९४२ शक संवत्)

#### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर (गाजियाबाद)

21 मार्च, 2020 ई0

सं0 1436 / न0पा0परि0खो0म0-विज्ञापन कर / 2019-20—नगरपालिका परिषद्, खोड़ा—मकनपुर, गाजियाबाद की सीमान्तर्गत विज्ञापन कर / शुल्क निर्धारण और वसूली व्यवस्था लागू करने हेतु निकाय की विशेष बोर्ड बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में पारित प्रस्ताव सं0-03, के द्वारा नगरपालिका बोर्ड की अनुमति के पश्चात् उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार यथा संशोधित करते हुये कार्यालय पत्र सं0 907 / न0पा0परि0खो0म0-विज्ञापन कर / 2019-20, दिनांक 08 नवम्बर, 2019 के द्वारा नगरपालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद में विज्ञापन कर / शुल्क उपविधि 2020 पर सुझाव / आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 09 नवम्बर, 2019 को दो दैनिक समाचार-पत्र शाह टाइम्स व हिन्दुस्तान में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी, जिस पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्रस्ताव सं0 03 के द्वारा सर्वसम्मित से निम्नलिखित नगरपालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद में विज्ञापन कर / शुल्क उपविधि 2020 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

#### उपविधि

#### 1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के सीमान्तर्गत विज्ञापन कर / शुल्क का निर्धारण और वसूली उपविधि 2020 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद की सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उपविधि 01 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

#### 2—परिभाषायें—

(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

[एक] ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ०प्र० अधिनियम सं०–2 सन् 1916) से है।

[दो] "नगरपालिका परिषद्" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर से है।

[तीन] "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

[चार] "प्रशासक / अध्यक्ष" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर के प्रशासक / अध्यक्ष से है।

[पांच] "प्रशासक / बोर्ड" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर के प्रशासक / निर्वाचित बोर्ड से है।

[छः] "निरीक्षणकर्ता" का तात्पर्य, कर अधीक्षक, कर एवं राजस्व निरीक्षक या अन्य अधिकारी से है, जिसे नगरपालिका परिषद् समय-समय पर अधिकृत करें।

[सात] ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने लिखित अनुमित प्रदान की गयी हो और ऐसे व्यक्तियों में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि और भवन का स्वामी भी सम्मिलित हो।

[आठ] "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक, माल जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो से संप्रदर्शित हो और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

[नौ] ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है।

[दस] "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है, जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।

[ग्यारह] ''झण्डी" का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है, जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।

[बारह]''झण्डी प्रतीक'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो।

[तेरह] ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है, जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं।

[चौदह] ''भू-प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो।

[पन्द्रह] ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्य प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो। [सोलह] ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना, वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से संबद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो, जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो।

[सत्रह] ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसी किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिली मीटर से अधिक बाहर की ओर हो।

[अट्ठारह] ''मार्गधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

[उन्नीस] ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परनिर्मित हो या रखा गया हो, जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

[बीस] ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न अनुसूची से है।

[इक्कीस] ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसे संरचना से है, जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो।

[बाईस] ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है।

[तेईस] ''अस्थायी प्रतीक'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढ़ांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

[चौबीस] ''बराण्डा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बराण्डा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है।

[पच्चीस] ''दीवार प्रतीक'' से तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है, जो किसी भवन या वाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हों।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हो।

#### 3-स्थल चयन के लिये समिति का गठन-

- (1) अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार के लिये ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिये नगरपालिका में एक समिति का गठन किया जायेगा।
  - (2) समिति में निम्नलिखित होंगे-

[1]	अधिशासी अधिकारी,	अध्यक्ष
[2]	नगर में यातायात का प्रभारी या नामित प्रतिनिधि (यातायात पुलिस विभाग),	सदस्य
[3]	परियोजना निदेशक, का नामित प्रतिनिधि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,	सदस्य
[4]	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का नामित प्रतिनिधि,	सदस्य
[5]	नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी,	सदस्य
[6]	परिवहन विभाग का एक अधिकारी / नामित प्रतिनिधि	सदस्य

[7] सचिव, विकास प्राधिकरण का नामित प्रतिनिधि

सदस्य

[8] उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि

सदस्य

[9] पालिका का यातायात अभियन्ता, अवर अभियन्ता या कोई अधिकारी

सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के अध्यक्ष, नगरपालिका द्वारा नामित चार सभासदगण, उपरोक्त समिति के सदस्य होंगे।

टिप्पणी-अधिशासी अधिकारी किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

- (3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों में, विज्ञापन कर / शुल्क की समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए, अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में, अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिये।
- (4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

#### 4-प्रतिषेध-

- (1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, (ट्री-गार्ड) नगर प्राचीर, बाउन्ट्रीवाल, नगर द्वारा, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा और न लटकायेगा।
- (2) नगरपालिका परिषद् की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।
- (3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन से अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।
- (4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा।
- (5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर नहीं प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- (6) नगरपालिका सीमान्तर्गत विभिन्न विभागों, प्राधिकरणों, परिषदों द्वारा निर्मित भवनों / भूखण्डों के क्षेत्र में (चाहे, वह नगरपालिका को हस्तान्तरित हो अथवा नहीं) विज्ञापन, अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ही किया जा सकेगा।
- (7) नगरपालिका सीमान्तर्गत नगरपालिका के अतिरिक्त किसी भी सरकारी (भारतीय रेलवे को छोड़कर) अर्द्धसरकारी, निजी स्थान, आर0डब्ल्यू०ए० इत्यादि को विज्ञापन के ठेके देने / प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा।

#### 5-अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

(1) अनुज्ञा प्राप्त के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर भरकर कार्यालय में नियत प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जायेगा या नगरपालिका के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रशीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन नियम 3(1) के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में लागू होगा।
- (3) यदि विज्ञापन किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा—
  - (क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार विवरण।
  - (ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना—संगणनाओं सिहत अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग 4 "संरचना अभिकल्प धारा 1 भार, बल और प्रभाव" के अनुसार होगा।

- (4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।
- (5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यति क्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर/शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा।
- (6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे, तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।
- (7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डी पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है, तो वह इस नियमावली के अधीन कर/शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।
- (8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो अधिशासी अधिकारी द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।
- (9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि की रसीद संलग्न होगी। 6—अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें—
- (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, विपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निर्बन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि—
  - [क] अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी, जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया है।
  - [ख] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगो और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्भृत किया जायेगा, जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिस्थापित किया गया हो की ऊंचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी 2 मीटर से कम नहीं होगी।
    - [ग] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।
    - [घ] प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।
  - [ङ] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

- [च] विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देगें या उसे मिटा देगें।
- [छः] विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिस्थापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे, या परिनिर्मित किये जायेंगे।
- [ज] (1) चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जेसे ग्रीनबेल्ट, पार्क, एल०एम०सी० भूमि, अन्य सरकारी एवं प्राईवेट भूमि पर लगाये गये विज्ञापन अवैध माने जायेंगे तथा इन विज्ञापनकर्ताओं के अवैध बोर्ड को हटाकर छः माह का वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।
- [झ] मार्ग के लिये खुली छोड़ी गयी भूमि, पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिये स्वत्रंत और सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।
- [ञ] भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और यातायात में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।
- [ट] लोकहित में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा। परन्तु उक्त कार्यवाही से पूर्व, अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारी को एक माह का पजीकृत नोटिस उत्तर दिये जाने हेतु दिया जायेगा। उक्त नोटिस में लोकहित का किस प्रकार उल्लंघन अनुज्ञाधारी द्वारा किया जा रहा है, स्पष्ट किया जायेगा। अनुज्ञाधारी का उत्तर प्राप्त होने पर उक्त उत्तर के परीक्षण उपरान्त ही अनुज्ञा-पत्र के निलम्बन पर निर्णय लिया जा सकेगा।
- [ठ] विज्ञापनकर्ता अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर नियमावली और विनियमावली का अनुपालन करेगा।
  - [ड] विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये।
- [ढ] भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों तथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।
- [ण] समस्त विज्ञापन नियम 16 "समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षायें" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।
  - [त] विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा।
- (2) अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण न किये जाने की निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुज्ञा समाप्त करने अथवा नवीनीकरण न किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारी को लिखित व पंजीकृत डाक से एक माह की अवधि में उत्तर दिये जाने की प्रत्याशा में कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।
  - [क] यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से गिर जाता है।
  - [ख] यदि कोई परिवर्धन, अधिशासी अधिकारी के निर्देशों के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है।
    - [ग] यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।
  - [घ] यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाता है, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्द्धन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है,

[ङ] यदि ऐसा भवन या संरचनाओं जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

#### 7—प्रीमियम—

- (1) न्यूनतम प्रीमियम धनराशि अधिशासी अधिकारी, द्वारा नियत की जायेगी।
- (2) न्यूनतम सात दिन का समय मुहर बंद लिफाफो में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये दिया जायेगा।
- (3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि की रसीद संलग्न होनी चाहिये।

#### 8-आवंटन समिति-

(1) अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में नगरपालिका परिषद् में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

[1] कर राजस्व अधिकारी,

सदस्य

[2] नगरपालिका का अवर अभियन्ता

सदस्य

[3] विज्ञापन पट्ट प्रभारी / कर अधीक्षक / राजस्व निरीक्षक,

सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, नगरपालिका द्वारा नामित 2 (दो) सभासदगण, उपरोक्त समिति के सदस्य होंगे।

- (2) समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदन करेगी।
- (3) नियम 26 के अधीन कर सिहत प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।
  - (4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।
- (5) विज्ञापनकर्ता द्वारा नगरपालिका को अनुमोदित प्रीमियम की 2 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी की जायेगी।
  - (6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबन्धन एवं शर्तें (नियम 5.6) अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।
- (7) नगरपालिका में विज्ञापन ठेके की एक न्यूनतम धनराशि निर्धारित की जायेगी। इस धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में निविदा के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा तथा ठेका स्वीकृत उपरान्त 10 दिन के अन्दर समस्त धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा।
- (8) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जायेगी।
- (9) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापनकर्ता द्वारा देय होगा।
- (10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहां नियम 18 के अधीन इसकी अनुज्ञा न हो) या ट्री-गार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा देय होगी।
- (11) जनहित के विज्ञापन (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार) पल्स पोलियों, मतदाता पहचान-पत्र, जागरूकता अभियान, साक्षरता मिशन, परिवार कल्याण आदि जन—उपयोगी सामाजिक सूचनाओं के विज्ञापन के लिये 20 प्रतिशत स्थल आरक्षित रखे जायेंगे। बी0ओ0टी0 (नई / पुरानी) के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष द्वारा नीति निर्धारित की जायेगी।

- (12) विद्युत पोलों पर बोर्ड की निर्धारित माप "30 x 40" से अधिक नहीं होगी।
- (13) पोस्टर एवं बेनर तथा वाल पेन्टिंग के ठेके नहीं किये जायेंगे। इससे दीवारों एवं नगर की सफाई, स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (14) नगरपालिका में प्रत्येक माह विज्ञापन पट्टों का भौतिक निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या पत्रावली पर रखी जाये।
- (15) विज्ञापन का आवंटन सीलबन्द निविदा के आधार पर किया जायेगा तथा तकनीकि एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक् रूप से डाली जायेगी।

#### 9—आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार-

नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है—

- (क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपित्तजनक प्रक्रिया का या नगरपालिका के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि अधिशासी अधिकारी की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपित्तजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।
- (ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।
  - (घ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
- (ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 128 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

## 10—अनुज्ञा प्रदान करने की रीति—

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखाने, करने या हस्तांतरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना अधिशासी अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा—

- (एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा
- (दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

#### 11-अनुज्ञा की अवधि-

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण के दिनांक से अनिधक दो वर्ष की अविध के लिये अनुज्ञा अधिशासी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अविध के लिये की जायेगी। तदानुसार ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीनीकरण किया जायेगा। तीन-तीन माह का नीवीनीकरण अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जायेगा।

#### 12-विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति-

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस नियमावली के उल्लघंन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय में या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अंशान्ति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभृति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है।

[एक] ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय।

[दो] ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लघंन के फलस्वरूप परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, के लिये क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षिति या विकृति को अधिशासी अधिकारी के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षितिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को नगरपालिका द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

#### 13-विज्ञापन पर निर्बन्धन-

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा।

[एक] यह आकार में 12.2 मीटर × 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भू-तल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

[दो] यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो। जो बी0ओ0टी0 है उन्हें छोड़कर नगरपालिका बोर्ड की अनुमति के बिना कोई बी0ओ0टी0 नहीं की जायेगी।

[तीन] यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

[चार] नियम-3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये अनुपयुक्त हो।

[पांच] यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी / पगडण्डी पर रखा गया हो।

[छः] यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

[सात] यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो।

[आठ] स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषद् या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो। (2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी-

[एक] ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुंचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो।

[दो] राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर।

[तीन] नियम 18 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर।

[चार] किसी लोक प्राधिकरण तथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिये परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

[पांच] ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिये परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न, व्यवधान उत्पन्न हो।

[छः] किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियों या पत्रक पर जिससे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिये परिसंकटमय हों।

[सात] ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उसकी दृश्यता बाधित हो।

[आठ] जब इनसे स्थानीय सुविधा प्रभावित हो।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी-

[एक] विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना तथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सिम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त हैं।

[दो] ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

[तीन] विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

## 14-छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन-

- (1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल वैध प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य हैं।
- (2) नियम 6 और नियम 13 के अधीन रहते हुये, किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई, नियम 15 (ग) (2) के अनुसार होगी।

#### 15-विज्ञापन तीन प्रकार के होंगे-

1-होर्डिंग्स 2-क्योस्क 3-यूनिपोल

#### 16-विज्ञापन पट्टों के प्रकार-विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के हैं-

- (क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन
- (ख) भू-विज्ञापन
- (ग) छत विज्ञापन
- (घ) बरामदा विज्ञापन
- (ङ) प्रक्षिप्त विज्ञापन
- (च) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
- (छ) आकाशीय विज्ञापन
- (ज) विविध और अस्थायी विज्ञापन

#### क-वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन-

क−1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री जहां विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट्ट अञ्चलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

क—2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन के भाग 8 भवन सेवायें धारा 2 विद्युत एवं सामग्री स्थापन, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क-3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षेतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जायेगा।

क—4 दो मंजिल से कम की ऊंचाई पर या पगडण्डी से 06 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो स्थिति सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से अवलम्बित किये जायेंगे, जिससे कि यातायात के नियंत्रण के लिये किसी विज्ञापन पट्ट या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रूप से रोका जा सके।

क—5—गहन प्रदीप्ति—कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा, जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती आवासीय भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिये दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् अधिशासी अधिकारी की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो को अधिशासी अधिकारी के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि जैसा कि अधिशासी अधिकारी विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा या उसे हटा दिया जायेगा।

क-6-**परिचालन अवधि**-लोक सौहार्द स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में अधिशासी अधिकारी की राय में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।

क-7-**चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला**-कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पिट्टका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार पिरिनिर्मित की जायेगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

#### (ख) भू-विज्ञापन-

ख—1—सामग्री—ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन, नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। ख-2-**आयाम**-भूमि से ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुखभाग से ऊपर जा सकता है।

ख–3–अवलम्ब और स्थिरक स्थान–प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख-4-स्थल सफाई-किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थो तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5**–यातायात में आपत्ति**–ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख—6—**तल निर्बाधन**—सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख-7-भू-चित्रित विज्ञापन-जहां प्रयोज्य हो वहां नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

#### (ग) छत विज्ञापन-

ग—1—सामग्री: नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढांचे, अवलम्बों और पटिट्यों सिहत प्रत्येक छत विज्ञापन पटिट्का को अज्जवलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जो के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और जहां ज्वलनशील सामग्रियां अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और निलंकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेगी।

ग-2-आयाम-कोई छत विज्ञापन ऊंचे भवनों पर निम्नलिखित ऊंचाईयों से अधिक नहीं होगा-

	भवन की ऊंचाई	विज्ञापन की ऊंचाई
(ক)	चार मंजिल या 18 मीटर से अनाधिक	02 मीटर
(ख)	पांच से आठ मंजिल या 18 मीटर से अधिक किन्तु 36 मीटर से अनाधिक	03 मीटर
(ग)	आठ मंजिल से अधिक या 36 मीटर परन्तु ऐसे विज्ञापनों की ऊंचाई की गणना	05 मीटर
	करने में उसी भवन के विभिन्न तलों पर एक दूसरे के ऊपर रखे गये या समतलों	
	पर रखे गये विज्ञापनों को एक विज्ञापन समझा जायेगा, चाहे ऐसे विज्ञापन विभिन्न	
	स्वामियों से सम्बन्धित हो या न हो।	

ग–3–**अवस्थिति**–(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नही रखा जायेगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न होगा।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नही रखा जायेगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अञ्जवलनशील सामग्री का न हो।

ग—4—**क्षेपण**—कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन के प्रक्षेपित नहीं होगा जिस पर यह परिनिर्मित हो या वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

ग—5—**अवलम्ब और स्थिरक**—प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जायेगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप से संवितरित होंगे।

ग—6—**चित्रित छत विज्ञापन, नियम 14**—समस्त विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जना चाहिये।

#### (घ) बरामदा विज्ञापन-

घ—1—**सामग्री—**प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 14 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

घ—2—आयाम—कोई बरामदा विज्ञापन ऊंचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मीटर से अधिक नहीं होगा। इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ-3-**सरेखण**-प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन, के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

घ—4—**स्थान—**बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगायी जायेगी—

- (एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गाटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।
- (दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टियां ऐसी मंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो।
  - (तीन) पेन्ट किये हुए विज्ञापन पटि्टकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।
- घ-5-**लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई**-किसी बरामदा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर पर हो।

घ—6—**प्रक्षेपण—**घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पटि्टका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नही होगी।

दीवार विज्ञापन पदार्थ—4 मीटर क्षेत्रफल से अधिक का प्रत्येक दीवार विज्ञापन पटि्टका नियम 14 के उपनियम (4) में दिये गये ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग में यथा उपबन्धित के सिवाये अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

- (एक) 'परिमाप' किसी दीवार विज्ञापन पिट्टका का कुल क्षेत्रफल 20 मीटर से अधिक नहीं होगा, सड़क के सामने जिधर ऐसी विज्ञापन पिट्टका का सामना पड़ता हो 15 मीटर के भवन, अग्रभाग के संबंध में प्रेक्षागृह या सिनेमा के नाम वाले किसी दीवार, विज्ञापन पिट्टका के मामले को छोड़कर ऐसे विज्ञापन पिट्टका का कुल क्षेत्रफल 200 मीटर से अधिक नहीं होगा।
- (दो) 30 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई दीवार विज्ञापन पट्टिका किसी ऐसी दीवार पर नहीं लगायी जायेगी जो सीधे सड़क के सामने न पड़ती परन्तु ऐसी विज्ञापन पट्टियों या विज्ञापन पट्टिकायें सड़क से दृश्यमान पार्श्व दीवार क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (तीन) प्रक्षेपण कोई भी दीवार विज्ञापन पट्टिका उस दीवार के जिससे वह लगी हो, शिखर के ऊपर या उसे अन्तिम छोर के बाहर नहीं निकली होगी। किसी ऐसे स्थान पर जहां पदयात्री किसी ऐसे दीवार के पास होकर गुजरते हो, लगी कोई विज्ञापन पट्टिका वहां से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी, जो ऐसे स्थान की सतह से 2.5 मीटर माप की ऊंचाई के भीतर होगी।

(चार) अवलम्ब एवं संलग्न—दीवारों से लगी प्रत्येक दीवार विज्ञापन पिट्टका सुरक्षित रूप से लगी होगी। लकड़ी के कुन्दे या स्क्रू-स्टेपल्स या कील के संबंध में प्रयुक्त लकड़ी के साथ स्थिरण को, लकड़ी की दीवारों से लगी दीवार विज्ञापन पिट्टकाओं के मामले को छोड़कर उचित स्थिरण नहीं माना जायेगा।

#### ङ-प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकायें-

ङ—1—**सामग्री—**प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थौ से निर्मित होगा।

ड-2-प्रक्षेपण एवं ऊँचाई-कोई भी प्रक्षेपण पिट्टका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाईन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

- (क) समस्त प्रक्षेपण पिट्टकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिनें कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी—निर्माण किया गया हो वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पिट्टका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।
- (ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओर के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग जिससे वह लगी हो के ऊपर नहीं निकली होगी।
  - (ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।
- ड-3-अवलम्ब एवं संलग्न-प्रत्येक प्रक्षेपण पिट्टका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचालन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, राडस, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हों, द्वारा रोका जा सकें और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सकें कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ पिरिस्थितिवश विज्ञापन पिट्टका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पिट्टका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।
- ड—4—अतिरिक्त भार—ऐसी प्रक्षेपण संबन्धी संरचनाएँ जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हो या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिये सक्षम होंगी, किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रिय क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रिय भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संगठक जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगायी जाये इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सकें।

#### च-शामियाना विज्ञापन पट्टिका-

च-1-**सामग्री**-शामियाना विज्ञापन पट्टिकाऍ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

च-2-**ऊँचाई-**ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होगी।

च–3–**लम्बाई**–शामियाना विज्ञापन पट्टिकाऍ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है। किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना को छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

#### छ:-आकाश विज्ञापन पट्टिका-

आकाश विज्ञापन पिट्टकाओं की दशा में ऐसी आकाश विज्ञापन पिट्टका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबन्धी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

#### ज-अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ, सचल सर्कल विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट-

ज-1-प्रकार-1.2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी—

- (क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उसके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।
- (ख) कोई ऐसी विज्ञापन पटि्टका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी वेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।
- (ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, वेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।
  - (घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पटिटका।
- (ड.) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।
- (च) कपड़े, पेपर मैच या सामान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाईसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएँ नहीं है।
- (छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये गये या प्रयोग किये जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पटि्टकाएँ जो किसी ब्रासप्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर या 450 मिलीमीटर से अनधिक हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो।
  - (ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

## ज-2-अस्थाई विज्ञापन पटि्टकाओं की आवश्यकता-

- (एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल, सर्कल और मेला चिन्ह और पटि्टकाएँ सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।
- (दो) ऐसी किसी विज्ञापन पिट्टका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबन्धित होगा जो उस पिरसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पिरिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पिट्टका को जैसे ही वह फट जाये या क्षतिग्रस्त हो जाये यथाशीघ्र और किसी भी दशा में पिरिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाये, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।
- (तीन) अधिशासी अधिकारी किसी अस्थायी विज्ञापन पिट्टका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए संशक्त होगा।
- (चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका**—पोल विज्ञापन पट्टिकाऍ पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाऍ स्ट्रीट लाईट के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हो।

- (पांच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पिट्टकाएँ— किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पिट्टकाएँ और झण्डियाँ जो कपड़े या ज्वलशील पदार्थ से निर्मित हों, सृदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलम्ब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाये या क्षतिग्रस्त हो जाये उन्हें यथाशीघ्र और पिरिनर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटाकाये जाने के लिए अस्थाई विज्ञापन पिट्टकाओं को अनुमित प्राप्त हो, 10 दिन की अवधि तक लटकाई जा सकती है
  - (छः) अधिकतम आकार अस्थाई विज्ञापन पटिटकाएँ क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।
- (सात) प्रक्षेपण—कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पिट्टकाएँ और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजिनक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसा चिन्ह पिट्टकाएँ बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।
- (आठ) विशेष अनुमित— भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झिण्डयाँ जो मार्ग या सार्वजिनक स्थलों के आर-पार बढ़े अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी।
- (नौ) नगर पालिका परिषद् द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिये प्रयोग में लाया जायेगा, जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी—मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबन्धित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

#### 17-सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएँ-

- (1) **भार**—विज्ञापन पट्टिकाएँ इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1 राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आधी, डेड से इस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।
- (2) कोई भी विज्ञापन पटि्टका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता-2005 के भाग-8, भवन सेवायें, खण्ड-2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी।
- (3) विज्ञापन पिट्टकाओं की डिजाईन और स्थान—(क) किसी भी विज्ञापन पिट्टकाओं से पद यात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्निशमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रुकावट नहीं आनी चाहिये।
  - (ख) किसी भी पटिटका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रुकावट नहीं आनी चाहिये।
- (ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिये। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका न लगायी जाये।
- (घ) अनावश्यक खम्भों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिये पट्टिकायें लाईटिंग फिक्सचर से युक्त होनी चाहिये।

- (ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकायें स्वाभाविक सभा-स्थलों पर लगायी जानी चाहिये और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- (च) जहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से वर्जित किया जाना चाहिये।
- (छः) विज्ञापन पट्टिकायें इस प्रकार लगायी जानी चाहिये जिससे कि सामने से और पीछे से पद यात्रियों का आवागमन सम्भव हो सके।
- (ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिये पठनीय बनाने के लिये विज्ञापन पटि्टका के किनारे बेल पटि्टयाँ लगायी जानी चाहिये या उभरे हुये अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
  - (झ) कोई भी विज्ञापन पटिटका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जानी चाहिये।
- (4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग—(एक) सजावटी विशिष्टता—ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिये जहाँ अनुमित हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पिट्टकाओं के लिये प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक के अन्य पदार्थ।
- (दो)—विज्ञापन पिट्टका का फलक—विज्ञापन पिट्टका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिये, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिये और विद्युत लाईटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिये और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के विकास के साथ संस्थापित होनी चाहिये।
- (5) विज्ञापन पिट्टकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण—जब भी कोई विज्ञापन पिट्टका हटायी जाये वह कार्य अधिशासी अधिकारी की नोटिस या उसके आदेश के कारण या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पिट्टका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति अधिशासी अधिकारी के संतोषप्रद रूप से की जायेगी। यदि विज्ञापन पिट्टका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजिनक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को नगर पालिका द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिये।
- (6) यातायात रोटरी क्लब और आईलैण्ड—अधिशासी अधिकारी अभिकरण को यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी, यातायात प्रभारी) के परामर्श से अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन के अनुसार यातायात रोटरी क्लबों व आईलैण्डों के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। सम्प्रदर्शन पट्ट का आकार यातायात रोटरी क्लब/आईलैण्ड के स्थान और आकार और यातायात की गित पर निर्भर करेगा। किन्तु सम्प्रदर्शन की ऊँचाई रोटरी क्लब/आईलैण्ड की ऊँचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।
- (7) मैदानों / पगडंडियों के किनारे रक्षक पिट्टयाँ— अधिशासी अधिकारी अभिकरण को मैदान / पगडंडी के किनारे रक्षक पिट्टयों की व्यवस्था करने व उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को अधिशासी अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित पिट्टयों पर नाम / उत्पाद को सम्प्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिये अधिशासी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने और अधिशासी अधिकारी के सन्तोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी / विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेंट करने के लिये आवद्धकर होगा।
- (8) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)—अधिशासी अधिकारी अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को अधिशासी अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम / उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

(9) पुष्प पात्र स्टैण्ड्स—अधिशासी अधिकारी किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 × 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दो और संप्रदर्शित किये जा सकते हैं परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिये।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजन के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

#### 18-ਾਲੂਟ-

#### (1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी।

- (एक) यदि किसी कार्यालय दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो। दुकान स्वामी द्वारा स्वयं का नाम, दुकान का नाम इत्यादि।
- (दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएं।
- (तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए।
- (चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन सम्प्रदर्शित सभी नोटिसें, परन्तु उनकी माप 0.60 मीटर × 0.60 मीटर से अधिक न हो।
- (पॉच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जायें किन्तु उसमें भवन या प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।
- (छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या करोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या अन्य वाहन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबन्धित हो, परन्तु यह 1.2 मीटर से अधिक न हो। विज्ञापन पट्टों के लिये, किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

## 2—दीवार विज्ञापन पट्ट—नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी—

- (एक) भण्डारण विज्ञापन पट्ट—िकसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या प्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचें और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।
- (दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट— किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(तीन) नाम पट्ट-किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

## 3-भू-विज्ञापन पट्ट-नीचे सूचीबद्ध भू-विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी-

- (एक) यात्रा मार्ग निर्देश—किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण या रख-रखाव, जो यात्रा मार्ग लाईन के स्थान, किसी रेलमार्ग, स्टेशन या अन्य सार्वजनिक वाहन को निर्दिष्ट करते हों जब वे क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हो।
- (दो) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट—सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों के विज्ञापन बिना अनुज्ञा के अनुज्ञेय है। यद्यपि वे नियम-13 के उपनियम (2) में दिये गये सिद्धान्तों के युक्तियुक्त रूप से अनुरूप हो।

#### 4-अस्थाई विज्ञापन पट्ट-

- (एक) निर्माण स्थल संकेत— निर्माण संकेत इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान (अनुसूची-3 देखें) के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जायें।
- (दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत—अवकोशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नित या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदेशन जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो परन्तु या कि अधिशासी अधिकारी किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तदायी नहीं है (नियम-15झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिये आवश्यकता देखिए।

5—अनुसूची-3 में दिये गये विज्ञापन पट्टों की गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं के लिये किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

#### 18-विशेष विज्ञापन-

- (1) यदि अनुसूची-2, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजिनक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो अधिशासी अधिकारी उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर जिसे वह उचित समझे, कर/शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, या लटाकने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।
- (2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विद्यमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर अवधि के लिये हो तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

#### 19-विशेष नियन्त्रण का क्षेत्र-

- (1) जब कभी अधिशासी अधिकारी की राय में इस नियमावली में निर्बन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षिति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर अधिशासी अधिकारी को अपील कर सकता है. जिसका विनिश्चय निर्णयक होगा।

- (3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होंगी, जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ''ज्वैलर्स'', ''कैफे'', ''डांसिंग'' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।
- (4) विशेष नियन्त्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उपनियम (3) में दिये गये, के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

#### 20-निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा-

नगर पालिका या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्ही क्षेत्र या किन्ही क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन, लगाना चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करे।

#### 21-झण्डियों पर रोक-

- (1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।
- (2) कोई भी अनुज्ञा नगर पालिका या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।
- (3) इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।
  - (4) अधिशासी अधिकारी इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे विनष्ट कर सकता है।

## 22-अनुरक्षण और निरीक्षण-

- (1) अनुरक्षण—सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों बंधनी रास्ता और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।
- (2) सुव्यवस्था—प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छोड़े गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
- (3) निरीक्षण—प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परिमट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परिमट अपेक्षित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

#### 23-प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति-

अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई नगर पालिका अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज पर्यवेक्षण माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत को या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है।

- (एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेत् कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।
- (दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
- (तीन) सदैव समुचित ध्यान दिया जायेगा जिससे कि ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं से स्पर्धा किया जा सके, जिसके लिये प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं के लिये प्रवेश दिया जाये।

#### 24-कर/शुल्क भुगतान की रीति-

अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर / शुल्क एकल किश्त में संदेह होगा, जबतक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

#### 25-क्षेत्रों का वर्गीकरण-

विज्ञापनों पर कर / शुल्क के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर के वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा—

- (एक) सर्वोचित वर्ग
- (दो) 'क' वर्ग
- (तीन) 'ख' वर्ग
- (चार) 'ग' वर्ग

#### 26-हटाये जाने की लागत-

नियम-12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी—

(ক)	6.1 मीटर × 3.05	मीटर या	उससे कम	के किसी	विज्ञापन र	या विज्ञापन प	ाट्ट के	5,000.00 रुपये
	हटाने की लागत							

- (ख) ऊपर खण्ड(क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं 8,000.00 रुपये विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत
- (ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत 2,000.00 रुपये
- (घ) निजी भवन पर(छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत 10,000.00 रुपये

#### 27-अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन-

- (1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन, ऐसे जुर्मानें से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन के दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।
- (2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनिधक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

#### अनुसूची-2

#### नियम-26 देखें

#### 1-विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर कर/शुल्क की दरें-

- नगर पालिका सीमान्तर्गत 60 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन पट्ट रु० 2,000.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष ।
- नगर पालिका सीमान्तर्गत 60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन पट्ट पर रु० 1,500.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशयुक्त द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो क्रमांक-1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

#### 2-विद्युत तथा अन्य खम्बों पर विज्ञापन पट्ट की दरें-

- नगर पालिका सीमान्तर्गत विद्युत खम्बों पर लगाये गये विज्ञापन पट्ट की माप 30" × 40" से अधिक नहीं होगी।
- नगर पालिका सीमान्तर्गत 60 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन-पट्ट पर रु० 2,000.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- नगर पालिका सीमान्तर्गत 60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन पट्ट पर रु० 1,500.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशयुक्त द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो क्रमांक-1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

## 3-यूनिपोल विज्ञापन की दरें-

- नगर पालिका सीमान्तर्गत 60 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर विज्ञापन पट्ट पर रु० 2,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष ।
- नगर पालिका सीमान्तर्गत 60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन पट्ट पर रु० 1,500.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष।
- यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशयुक्त द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो क्रमांक-1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

## 4-शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन कर (व्यावसायिक विज्ञापन वाहन)-

- हल्का वाहन रु० ५,०००.०० प्रतिवर्ष प्रति वाहन
- भारी वाहन रु० 10,000.00 प्रतिवर्ष प्रति वाहन
- 5—दुकान स्वामियों द्वारा अपना स्वयं का नाम (व्यावसायिक प्रकार को छोड़कर) का बोर्ड लगाने पर कोई विज्ञापन कर देय नहीं होगा। दुकान स्वामियों द्वारा दुकान / प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक विज्ञापन पट्ट लगाने पर रु० 100.00 स्क्वायर बोर्ड पर, फुट सामान्य रु० 150.00 स्क्वायर फुट प्रकाशमान बोर्ड पर देय होगा।

रीना देवी, अध्यक्ष, न0पा0परि० खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद।

## कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, मिलक, जनपद रामपुर

24 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 894 / मू०क0-विनियम-01 / 2019, 18 नवम्बर, 2019—नगरपालिका परिषद्, मिलक ने अपने विशेष संकल्प संख्या 2 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 द्वारा उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 297 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के आधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिवेशनों का आयोजन, सम्पादित कार्यों का विनियमन एवं समितियों का गठन और कर्तव्य विषयक विनियम बनाये हैं जो नगरपालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2019 विशेष प्रस्ताव सं० 2 में सर्वसम्मित से स्वीकृत कर सरकारी गजट में प्रकाशित कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः यथा संकल्पित विनियम उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अनुसरण में प्रकाशित किये जाते हैं :

#### विनियम

नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिवेशनों का आयोजन, सत्पादित कार्यों का विनियमन एवं समितियों का गठन और कर्तव्य विनियम

(अन्तर्गत उ०प्र०, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 297 (1) खण्ड (क) से (घ) तक)

- **1—शीर्ष, प्रसार एवं प्रारम्भ**—(1) यह विनियम, नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद रामपुर के अधिवेंशनों का आयोजन, सम्पादित कार्यों का विनियमन एवं समितियों का गठन और कर्त्तव्य विनियम, 2019 कहलायेंगे।
  - (2) यह नगरपालिका परिषद्, मिलक में लागू होंगे।
  - (3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

#### 2-परिभाषाऐं-विषय पर प्रसंग में कोई बात प्रतिभूत न होने पर इन विनियमों में-

- (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
- (ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिशासी अधिकारी से है।
- (ग) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक से है।
- (घ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक के अध्यक्ष से है।

# 3—नगरपालिका के अधिवेशनों के आयोजन तथा अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन (धारा 297 (1) (क) ) —

- (1) प्रत्येक माह की 15 तारीख को अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये समय और स्थान पर नगरपालिका की एक बैठक आयोजित की जायेगी उस दिन अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को बैठक आयोजित की जायेगी। 4—बैठकों को आयोजित करने की रीति तथा उसकी सूचना देना (धारा 297 (1) (ख))—
- (1) किसी बैठक के तीन दिनों से पूर्व—बैठक में उपस्थित होने की एक सूचना जिस पर अधिशासी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जायेगी।
- (2) किसी बैठक के उपस्थित होने की किसी सूचना में बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव या समस्या का निवेश होगा जिसके साथ-साथ अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (6) में उल्लिखित मामले में उक्त उपधारा द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त ब्योरे होंगे और सामान्यतयः उसमें सम्पादित किये जाने वाले किसी अन्य कार्य का उल्लेख होगा।
  - (3) किसी बैठक में उपस्थित होने की प्रत्येक सूचना में स्थान, दिनांक तथा बैठक के समय का उल्लेख होगा।
- (4) जहां तक परिस्थितियां अनुमित दें अधिशासी अधिकारी किसी बैठक के यथाशीघ्र पूर्व बैठक में सम्पादित किये जाने वाले किसी कार्य से सम्बन्धित ऐसे पत्राचार को, जिसे अध्यक्ष वांछनीय समझे कि बैठक के पूर्व उसके अनुशीलन का अवसर उन्हें मिलना चाहिये, सदस्यों को परिचालित करेगा।

## 5—बैठकों की कार्यवाहियों का संचालन तथा बैठकों का स्थगन (धारा 297 (1) (ग) ) —

(1) कोई सदस्य जो, किसी समय किसी प्रस्ताव या समस्या को प्रस्तुत करना चाहता है वह माह की 05 तारीख तक इस आशय की लिखित सूचना अध्यक्ष को देगा।

- (2) कोई भी सदस्य अध्यक्ष को नियमावली प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसे किसी विषय में कोई चर्चा नहीं की जायेगी जब तक कि अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों की सहमति से उस पर विचार किया जाना उचित समझे।
  - (3) प्रत्येक प्रस्ताव या संशोधन लिखित रूप में प्रस्तृत किया जायेगा या लिख कर लिया जायेगा।
- (4) अध्यक्ष यह अपेक्षा कर सकता है कि किसी प्रस्ताव या प्रस्तावित संशोधन का, उस पर चर्चा से पूर्व समर्थन किया जायेगा।
- (5) किसी प्रश्न का प्रस्ताव करते या चर्चा करते हुये प्रत्येक सदस्य अपने स्थान से ही बोलेगा और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा।
- (6) कोई भी सदस्य सिवाय प्रस्तावक के, अध्यक्ष की अनुमित के बिना उत्तर देने में किसी प्रस्ताव या संशोधन पर दो बार नहीं बोलेगा।
- (7) बैठक की कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों को एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच अध्यक्ष के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जायेगा।
  - (8) कार्यक्रम जब तक कि अध्यक्ष इसको अन्यथा विनियमित न करें, निम्नलिखित क्रम में होगा।
    - (क) विगत बैठक की कार्यवाही को पढा जायेगा।
    - (ख) यदि बैठक मास में आयोजित प्रथम बैठक हो तो विगत मास का लेखा नगरपालिका परिषद् के विचार तथा आदेशों लिये प्रस्तुत किया जायेगा।
    - (ग) राज्य सरकार तथा सरकार के अधिकारियों से पत्र व्यवहार को पढ़ा जायेगा।
    - (घ) समितियों तथा सदस्यों की रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा और आदेश, जहां आवश्यक हो, पारित किये जायेंगे।
    - (ङ) उन प्रस्तावों तथा समस्याओं, जिनकी सूचना उपरोक्त विनियम 4(2) द्वारा विहित रीति से दी गयी हो, पर चर्चा होगी और मतदान होगा।
    - (च) कोई प्रस्ताव या समस्या, जिसको अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित हो, की सूचना दी जायेगी।
    - (छ) समितियों, अधिकारियों आदि के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निस्तारण किया जायेगा, यदि यह शक्ति प्रत्यायोजित न की गई हो।
    - (ज) अन्य विषय-
- (9) विनियम 5(8) में किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होगी कि वह विनियम 4(2) के अधीन दी गई सूचना में किसी प्रस्ताव या समस्या, जिसका विनिर्देश या कार्यवाही जिसका उल्लेख न किया गया हो और जो इतना महत्वपूर्ण हो कि उस पर बैठक में कार्यवाही को उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा आवश्यक समझा जाता हो प्रस्तुत कर सकेगा।
- (10) (क) जब तक कि किसी बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती है, अध्यक्ष द्वारा बैठक में की गई घोषणा कि कोई संकल्प पारित हो गया है, इस आशय की कोई प्रविष्ट अधिनियम की धारा 94 के अधीन रखी गयी कार्यवृत्त पुस्तक में किये जाने के लिये प्रयप्ति आधार होगा।
- (ख) यदि उपस्थित किसी सदस्य द्वारा मतदान की मांग की जाती है तो मतदान को हाथ उठाकर किया जायेगा और ऐसे मतदान के परिणाम को बैठक में नगरपालिका परिषद् की संकल्प होना माना जायेगा।
- (11) किसी स्थिगत बैठक में, उस बैठक जिस में स्थिगन किया गया था, के अपूर्ण छोड़े गये कार्य से भिन्न कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी किन्तु इस विनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी अन्य बैठक के समान ही उस दिन किसी स्थिगत बैठक का किया जाना नहीं होने दिया जायेगा।
- 06—प्रश्नों का पूछा जाना—नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार होगा जिसका प्रयोग निम्नलिखित शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन किया जा सकता है (धारा 297 (1) (ग) )—
- (1) प्रत्येक सदस्य जो नगरपालिका के मामलों से सम्बन्धित कोई प्रश्न पूछना चाहता है, नगरपालिका को अगली साधारण बैठक के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व अधिशासी अधिकारी को अपने प्रश्न या प्रश्नों को लिखित रूप में भेजेगा।

- (2) इस प्रकार प्राप्त किये गये प्रश्नों को उनकी प्राप्ति के दिनांक के क्रम में अधिशासी अधिकारी द्वारा संख्यांकित किया जायेगा और बैठक की कार्य सूची में उनके क्रम संख्या के क्रम में अन्ततः स्थापित किया जायेगा।
- (3) प्रश्नों के प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी उनको अध्यक्ष नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अध्यक्ष प्राप्त प्रश्नों के उत्तरों को तैयार करने के लिये नगरपालिका के किसी अधिकारी या किसी समिति के सभापित को निर्देश दे सकता है।
  - (4) प्रश्नों को विवादी या कल्पित या समाज के किसी व्यक्ति या वर्ग का निन्दात्मक नहीं होना चाहिये।
- (5) नगरपालिका अध्यक्ष किसी प्रश्न को जो उपर्युक्त विनियम (4) के अनुरूप न हो, अस्वीकार कर सकता है और ऐसे किसी स्थिति में प्रश्नों की प्रविष्टि कार्यवृत्त में नहीं की जायेगी।
- (6) नगरपालिका की अगली बैठक में अध्यक्ष या उसकी अनुमित से अधिशासी अधिकारी या नगरपालिका का कोई अधिकारी जिसके विभाग से प्रश्न का सीधा सम्बन्ध हो या किसी समिति का सभापित बैठक के पूर्व समयक् रूप से प्राप्त प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेगा।
- (7) प्रश्न तथा उन के उत्तर बैठक की कार्यवाही के भाग होंगे और कार्यवृत्त के साथ-साथ प्रकाशित किये जायेंगे जब तक कि किसी विशेष मामलें में नगरपालिका परिषद् अन्यथा निर्देश न दें।
- (8) प्रश्न पूछने वाला सदस्य बैठक में उत्तर पढ़े जाने के पूर्व किसी भी समय उसको वापस ले सकता है किन्तु किसी ऐसे मामले में प्रश्न को कार्यवृत्त से निकाल दिया जायेगा।
- (9) यदि सदस्य, जिसने किसी प्रश्न को सम्यक् सूचना दे दी हो, बैठक आयोजित होने के पूर्व प्रश्न को वापस न लिया हो किन्तु बैठक में उपस्थित न हो तो अध्यक्ष किसी अन्य उपस्थित सदस्य को प्रश्न पूछने और उसका उत्तर पढ़े जाने की अनुमति दे सकता है।

#### 07-समितियां बनाना, उनका गठन तथा समितियों के कर्त्तव्य (धारा 297 (1) (घ) )-

- (1) नगरपालिका की निम्नलिखित समितियां होगी-
  - (क) वित्त एवं राजस्व समिति।
  - (ख) लोक निर्माण समिति।
  - (ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति।
  - (घ) जल कल एवं पथ प्रकाश समिति।
- (2) प्रत्येक समिति के पांच सदस्य होंगे जो अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथा उपबन्धित एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुने जायेंगे।
- (3) कोई भी व्यक्ति एक या अधिक समितियों का सदस्य हो सकता है। व्यक्ति का तात्पर्य अधिनियम की धारा 105 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है।
- (4) प्रत्येक समिति के सदस्य पद धारण करने के लिये प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में चुने जायेंगे जो एक वर्ष के लिये या आगामी जनवरी में नये सदस्यों के चयन तक, जो भी अवधि कम हो, रहेंगे।
- (5) यदि कोई बैठक आयोजित की जाती है और सभापित अनुपस्थित होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को बैठक का सभापित चुन लेंगे।

#### 9-समितियों के कर्त्तव्य समितियों के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे-

#### (क) वित्त एवं राजस्व समिति के कर्त्तव्य-

- (1) आय और व्यय का वार्षिक अनुमान तैयार करना।
- (2) विभिन्न शीर्षकों के अधीन व्यय के लिये स्वीकृत बजट अनुमानों के भीतर निधियों का आवंटन करना।
- (3) स्वयं यह समाधान करना कि कोई व्यय सिवाय उचित स्वीकृति के अधीन और बजट अनुमानों तथा आवंटनों को नहीं किया गया है या किया जा रहा है।
- (4) नगरपालिका परिषद् को प्रस्तुत करने के पूर्व मासिक लेखा का परीक्षण करना।
- (5) वसूली अधिष्टान के कार्य का निरीक्षण करना और उनके लेखा की जांच करना।

- (6) यह देखना कि संविदाओं से सम्बन्धित अधिनियम को धाराओं 96 से 98 तक के उपबन्धों का पालन सम्यक् रूप से किया जाता है।
- (7) यह देखना कि समस्त विभागों की माल बाईयों तथा भण्डार लेखा और उपकरणों तथा संयन्त्र के रिजस्टर नगरपालिका परिषद् लेखा नियमावली द्वारा विहित रीति से रखे जाते हैं और नगरपालिका परिषद् के समस्त माल तथा सम्पत्ति का सत्यापन समय-समय पर किया जाता है।
- (8) वित्त से सम्बन्धित ऐसे समस्त विषयों में सामान्यतः नगरपालिका परिषद् को परामर्श देना जो समय-समय पर उसको निर्दिष्ट किये जाये।
- (9) अधिनियम की धारा 112 के अधीन नगरपालिका परिषद् की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का निर्वहन करना।
- (10) यह देखना कि कर विभाग से सम्बन्धित नियमों, उपविधियों और आदेशों का पालन किया जाता है और नियोजित कर्मचारी अपने कर्तव्यों को नियमित तथा सन्तोषप्रद रूप से निर्वहन करते है।
- (11) नगरपालिका के निजी स्रोत्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि करने के सम्बन्ध में परामर्श देना।
- (12) नगरपालिका को चल और अंचल सम्पत्ति की देख-रेख करना, उस की सुरक्षा के उपाय तथा सम्पत्ति से प्राप्त होने वाले राजस्व / किराया में वृद्धि हेत् परामर्श देना।
- (13) करों, शुल्कों तथा अन्य राजस्व की वसूली में सहयोग देना।
- (14) अचल सम्पत्ति, रजिस्टरों की प्रविष्टियों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से कराना।

#### (ख) लोक निर्माण समिति के कर्तव्य-

- (1) लोक निर्माण कार्यों के लिये समस्त आवंटनों के व्यय पर विचार करना और प्रस्तावों को तैयार करना।
- (2) अभियन्ता / अवर अभियन्ता से उक्त कार्यों के लिये अनुमानों को मांगना और उनका परीक्षण करना तथा उस क्रम के सम्बन्ध में जिसमें ऐसे निर्माण कार्यों को किया जाना चाहिये, संस्तुति करना।
- (3) यह देखना कि माप पंजियों को उचित रूप से रखा जाता है तथा जारी निर्माण कार्यों और किये गये निर्माण कार्यों की सामान्य रूप से सूचना देना।
- (4) लोक निर्माण कार्यों के समापन प्रमाण-पत्रों का परीक्षण और जांच करना।
- (5) बिलों का परीक्षण करना।
- (6) ऐसे निर्माण कार्यों के लिये जिनका अनुमोदन नगरपालिका परिषद् द्वारा कर दिया गया हो, ऐसी निधियों का आवंटन करना जो समय-समय पर उसके अधीन रखी जाये।
- (7) ऐसे समस्त लोक निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये जिनकों संविदा पर किया जाना हो, निविदायें आमंत्रित करना और किसी निविदा को स्वीकृत किये जाने के लिये ली जाने वाली प्रति भूति के सम्बन्ध में परामर्श देना।
- (8) एक भाव अनुसूची रखना और समय-समय पर उनका पुनरीक्षित करना।
- (9) यह देखना कि लघु निर्माण कार्य जिनकी सम्भावित लागत रु० 5,000.00 से कम हो, से भिन्न प्रत्येक निर्माण कार्य के विस्तृत रेखा चित्र तथा अनुमानों को तैयार किया जाता है और उचित प्राधिकारी द्वारा पहले ही स्वीकृति दे दी जाती है।
- (10) यह देखना कि स्वीकृत निर्माण कार्यों का आरम्भ और निष्पादन विस्तृत रेखा-चित्रों तथा अनुमानों के अनुसार किया जाता है और जहां उनको संविदा पर दिया जाता है संविदा विलेख की शर्तों के अनुसार किया जाता है तथा उन शर्तों के किसी अंग के लिये संविदाकार से अपेक्षा की जाने वाली शक्ति के सम्बन्ध में परामर्श देना।

- (11) यह देखना कि माल बहियों तथा उपकरणों एवं संयन्त्रों के रिजस्टर को बनाये रखा जाता है और यह कि लोक निर्माण विभाग के माल तथा सम्पत्ति का समय-समय पर सत्यापन किया जाता है।
- (12) नगरपालिका परिषद्, मिलक को सामान्यतः लोक निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समस्त विषयों में परामर्श देना।
- (13) अधिनियम की धारा 112 के अधीन नगरपालिका परिषद् की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का निर्वहन करना।

#### (ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति के कर्तव्य-

- (1) यह देखना कि सफाई व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त नियमों, उपविधियों तथा आदेशों का पालन किया जाता है और यह कि सफाई आयोजन के लिये नियोजित कर्मचारी अपने कर्तव्यों को नियमित तथा सन्तोषप्रद रूप से निर्वहन करते हैं।
- (2) समय-समय पर सफाई कर्मचारी वर्ग की पर्याप्तता के सम्बन्ध में सूचना देना और यह देखना कि विशेष आदेशों कि बिना स्वीकृति अधिष्टान में वृद्धि नहीं की जाती है।
- (3) सफाई विभाग के कार्य के समस्त संचालन के लिये अपेक्षित सामानों की मात्रा तथा प्रकार के सम्बन्ध में परामर्श देना।
- (4) सार्वजनिक, कुऐं, घाटियां, शौचालय, सामान्य सफाई गाड़ी तथा उपस्कर आदि का निरीक्षण करना और स्थिति की सूचना देना।
- (5) जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के रजिस्ट्रीकरण की जांच करना।
- (6) टीका अधिनियम की गतिविधि की निगरानी करना।
- (7) नगरपालिका परिषद् को सामान्यतः स्वच्छता, सफाई तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित विषयों में परामर्श देना।
- (8) अधिनियम की धारा 112 के अधीन नगरपालिका परिषद् की प्रत्यायोगित शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का निवर्हन करना।

#### (घ) जलकल एवं पथ प्रकाश, समिति के कर्तव्यों-

- (1) यह देखना कि जलकल संचालन से सम्बन्धित नियमों और आदेशों का पालन किया जाता है और नियोजित कर्मचारी अपने कर्तव्यों को नियमित तथा सन्तोषप्रद रूप से निर्वहन करते हैं।
- (2) जलकल एवं पथ प्रकाश व्यवस्था संचालन हेतु आंवटित बजट धनराशि के अनुसार व्यय के आंकलन प्रस्तुत करना।
- (3) जलकल एवं पथ प्रकाश व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु मशीनों उपकरणों तथा सामान आदि की अपेक्षित यात्रा के बारे में परामर्श देना।
- (4) सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमानुसार सार्वजनिक पेयजल बम्बों (वाटर स्टैण्ड पोस्ट) को संचालित रखने पर नियंत्रण रखना।
- (5) जलकल एवं पथ प्रकाश व्यवस्था में सुधार तथा विकास हेतु परामर्श देना।
- (6) अधिनियम की धारा 112 के अधीन नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रत्यायोगित शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का निर्वहन करना।
- (7) जलापूर्ति व्यवस्था को सन्तोषजनक बनाये रखने तथा जल मूल्य की वसूली में सहयोग देना।

केतकी देवी अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, मिलक।

## कार्यालय, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ़ बोर्ड, लखनऊ

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2020 ई0

वक्फ़ संख्या 27 से 41 व 44 हरदोई के मुतवल्ली श्री मों0 खालिद का कार्यकाल समाप्त हो जाने तथा कार्यकाल में वृद्धि किये जाने हेतु श्री मों0 खालिद का प्रार्थना-पत्र बोर्ड द्वारा खारिज कर दिये जाने व उन वक्फ़ों की तौलियत हेतु कोई उचित व्यक्ति मुतवल्ली पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध न होने के कारण उ०प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड, लखनऊ ने धारा 65 वक्फ़ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने आदेश दिनांक 24 नवम्बर, 2020 द्वारा उपरोक्त वक्फ़ों को एक वर्ष की अवधि अथवा किसी उपयुक्त मुतवल्ली / कमेटी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, बोर्ड के सीधे नियन्त्रण में लेते हुये श्री हफीजुर्रहमान, कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड, लखनऊ को उसके प्रबन्ध हेतु प्रशासक नियुक्त किया है।

ताजदार आलम, सहायक सचिव, उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड, 3-ए, माल एवेन्यू, लखनऊ।

#### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप डीड, दिनांक 16 जुलाई, 2002 के द्वारा साझीदार 1–मनीष कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार पता-ई-16, जंगपुरा एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110014, उ०प्र०, 2—श्रीमती सुवा देवी पत्नी स्व0 पुभुदयाल, निवासी ई-16, जंगपुरा एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110014 जिनके द्वारा फर्म मेसर्स रिलायबल इण्डस्ट्रीज सी-34, 35, इण्डस्ट्रियल एरिया, सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर, उ०प्र०, ब्रान्च ऑफिस ई-16, जंगपुरा एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110014 का पंजीयन उपनिबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा संख्या 311 / पंजीकरण संख्या 28198-एम, दिनांक 29 जून, 2015 में किया गया था। फर्म साझेदारी दिनांक 23 जुलाई, 2017 से नवीन साझीदार की हैसियत से फर्म भागेदारी में श्रीमती पूनम अग्रवाल सम्मिलित ह्यी थीं व फर्म साझीदार 2–श्रीमती सुवा देवी फर्म साझेदारी से अपनी पूर्ण सहमति व स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गयी थीं। फर्म की सेवानिवृत्त साझेदार श्रीमती सुवा देवी की दिनांक 25 जुलाई, 2017 में मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में फर्म साझेदार 1–श्री मनीष कुमार अग्रवाल, 2–श्रीमती पूनम अग्रवाल हैं।

> मनीष कुमार अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, साझीदार, मेसर्स रिलायबल, इण्डस्ट्रीज रजि०।

#### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यूनीवर्सल इन्डस्ट्रीज स्थित घटपुरी, जिला बदायूं (उ०प्र०) द्वारा श्रवण कुमार घटपुरी, जिला बदायूं (उ०प्र०) पिन कोड-243601 फर्म पंजीकरण संख्या बी-10315 के कुल चार साझेदार (1) श्रवण कुमार सिंह पुत्र अमर पाल सिंह, (2) अमर पाल सिंह पुत्र देशराज सिंह, (3) श्री संदीप कुमार सिंह पुत्र अमरपाल सिंह, (4) कल्लू सिंह उर्फ कल्याण सिंह थे। फर्म के तीन साझेदार अमरपाल सिंह पुत्र देशराज सिंह, संदीप कुमार सिंह पुत्र अमरपाल सिंह व कल्लू सिंह उर्फ कल्यान सिंह ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 31 मार्च, 2019 को फर्म से अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग कर लिया है तथा उपरोक्त फर्म में नये साझेदार धीरेन्द्र पाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह, निवासी घटपुरी, जिला बदायूं (उ०प्र०) नियुक्त किये गये हैं। अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी भी प्रकार का साझेदारों का फर्म पर या साझेदारों पर कोई लेना-देना बकाया नहीं रह गया है। अब फर्म में साझेदार श्रवण कुमार सिंह व नवनियुक्त साझेदार धीरेन्द्र पाल सिंह हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

> श्रवण कुमार सिंह, साझेदार, फर्म मेसर्स यूनीवर्सल इन्डस्ट्रीज, स्थित घटपुरी, जिला बदायुं (उ०प्र०)।

#### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ सव्यसाची मिश्र के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्रमाण-पत्रों में मेरे जैविक माता-पिता श्रीमती सुधा मिश्र एवं राजेन्द्र नाथ मिश्र का ही नाम अंकित है। दिनांक 24 सितम्बर, 2011 को सबरजिस्ट्रार कचहरी, वाराणसी के समक्ष सम्पन्न रजिस्टर्ड गोदनामें को संज्ञान में लेकर नियमानुसार मेरी (सव्यसाची मिश्र की) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय. वाराणसी की उपाधियों स्नातकोत्तर) तथा अन्य प्रमाण-पत्रों (जे०आर०एफ०, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) में मेरी ग्राहिता विद्योत्तमा मिश्र का नाम माता / एकल अभिभावक के रूप में अंकित हो चुका है। मेरी (सव्यसाची मिश्र की) आगामी सभी उपाधियों एवं प्रमाण-पत्रों में मेरी ग्राहिता विद्योत्तमा मिश्र का ही नाम मेरी माता / एकल अभिभावक रूप में अंकित रहेगा। मेरा अपने जैविक माता-पिता से भविष्य में भी कोई सरोकार नहीं रहेगा।

> सव्यसाची मिश्र, बी 31 / 40 बी-2-एल, भोगाबीर, लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

#### सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण-पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड में मेरा नाम बृजेश कुमार है। मेरे पिता स्व0 कल्लू के परिवार तालिका में बृजेश अंकित है। बृजेश एवं बृजेश कुमार एक ही व्यक्ति हैं। भविष्य में मुझे बृजेश कुमार के नाम से ही जाना पहचाना जाये। कराहा तालाब, आनापुर, प्रयागराज।

> बृजेश कुमार, पुत्र स्व० कल्लू, पता—कराहा तालाब, आनापुर, प्रयागराज।

#### सूचना

फर्म मेसर्स-एम0के0 ट्रांसपोर्ट, 02 शाहपुर पनकी, पंक बहादुर नगर, गंगागंज, कानपुर नगर में फर्म उपरोक्त में श्री मनीष सिंह वर्मा पुत्र स्व0 शंकर लाल वर्मा, नि0 02 शाहपुर पनकी, पंक बहादुर नगर, कानपुर नगर का स्वर्गवास दिनांक 30 जून, 2020 को हो गया है तथा दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को श्रीमती सरोजनी पत्नी स्व0 शंकर लाल पुत्री श्री देवी गुलाम, नि0 02 शाहपुर पनकी, पंक बहादुर नगर, गंगागंज, कानपुर नगर सिम्मिलित हो गयी हैं।

विनोद कुमार वर्मा, पार्टनर, मेसर्स-एम०के० ट्रांसपोर्ट, 02 शाहपुर पनकी, पंक बहादुर नगर, गंगागंज, कानपुर नगर।